

[2016] 9 एस.सी.आर. 985

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

संतोष गुप्ता एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 12237-12238/2016)

16 दिसंबर, 2016

[कुरियन जोसेफ और आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्तिगण]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन। 3 (1) और (4) 17 क और 18 ख - अधिनियम का अनुप्रयोग - जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए- क्या संसद की विधायी क्षमता के भीतर अधिनियम के रूप में 'संपत्ति के हस्तांतरण' से संबंधित है न कि 'बैंकिंग' और यह जम्मू और कश्मीर के संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 के साथ सीधे संघर्ष में है; और क्या अधिनियम की धाराएं 17क और 18ख, न्याय प्रशासन (जो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है) से संबंधित प्रावधान होने के कारण भी अधिकार से बाहर होगा संसद- अभिनिर्धारित: जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है जम्मू और कश्मीर आदेश, 1954 को लागू होने वाले संविधान के अनुसार, राज्य कुछ संशोधनों और संशोधनों के साथ भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को अपनाता है- अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टियां 45 और 95 जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू की गई हैं- बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 45 के अंतर्गत आती है- यह अधिनियम सूची की प्रविष्टि 45 से संबंधित है- राज्य सूची के तहत किए गए किसी भी अधिनियम को अनुप्रयोग के आधार पर भारत के संविधान के प्रावधानों को प्रभाव देना होगा भारत के संविधान का 246 के आधार पर - सार और सार में पूरा अधिनियम प्रविष्टि 45 के लिए संदर्भित है सूची । सह पठित प्रविष्टि 95 सूची ।- यह अधिनियम 'संपत्ति के हस्तांतरण' से संबंधित नहीं है- बिक्री या हस्तांतरण के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण, बैंक के कारण सुरक्षित ऋण की वसूली के कई उपायों में से एक है- पहले किसी अधिनियम को विभिन्न भागों में विच्छेदित करना और फिर उन भागों को विधायी सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए निर्दिष्ट करना सही नहीं है- धाराएं 17क और 18ख, भी प्रविष्टि 45 के लिए और स्पष्ट रूप से सूची । की प्रविष्टि 95 के लिए

संदर्भित हैं। 17क और 18ख सूची । की प्रविष्टियों 45 और 95 के लिए संदर्भित हैं - इसलिए समग्र रूप से अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्य करेगा- अनुच्छेद 246 के आधार पर, जम्मू और कश्मीर के संविधान के सह पठित धारा 5, जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के धारा 140 को आक्षेपित अधिनियम को रास्ता देना है- आक्षेपित अधिनियम संसद की विधायी क्षमता के भीतर है- भारत का संविधान- अनुच्छेद 1, 246 और 370, अनुसूची VII सूची । प्रविष्टि 45 और 95- जम्मू- कश्मीर का संविधान धारा 3 और 5- जम्मू और कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1977- धारा 140-प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002-r.8 (5) प्रावधान।

भारत का संविधान:

अनुच्छेद 368 प्रावधान, 370 (1) (घ) अनुसूची VII , राज्य सूची- क्या जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा मूल रूप से अपनाई गई राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर रोक लगा दी गई थी और जब तक अनुच्छेद 370 (1) (घ) अनुसूची VII, राज्य सूची- क्या मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा अपनाई गई राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर रोक लगा दी गई थी और इसे कभी भी संसद को प्रत्यायोजित या प्रदान नहीं किया जा सकता है। 370 अवशेष- अभिनिर्धारित: अनुच्छेद 368 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू हैं किसी भी संवैधानिक संशोधन को राज्य की सहमति से लागू करने की अनुमति देता है- संशोधन में राज्य सूची में 'जोड़' या 'घटाव' शामिल होगा। - अनुच्छेद में होने वाले 'अभिव्यक्ति' परिवर्तन। 370 (1) (घ) का अर्थ 'सीमित करना या प्रतिबंधित करना' नहीं होगा, बल्कि 'विस्तार करना या बढ़ाना' भी होगा- 'संशोधन' शब्द का व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 368 प्रावधान और अनुच्छेद 370- संविधान संशोधन- जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू- अभिनिर्धारित: अनुच्छेद 370 के अनुसार। एक बार जब संघ सूची या समवर्ती सूची से कोई मामला राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो राज्य की और सहमति की आवश्यकता नहीं होती है- एक संवैधानिक संशोधन एक सामान्य कानून से अलग है- अनुच्छेद 368 के प्रावधान की भाषा अनुच्छेद 370 की भाषा से अलग और उनकी शर्तों के अनुसार लागू किया जाना है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1 यह कहना सही नहीं है कि भारत के संविधान और जम्मू और कश्मीर के

संविधान को समान दर्जा प्राप्त है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 और जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि भारत राज्यों का संघ होगा और जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। जम्मू और कश्मीर राज्य, हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अर्थ के भीतर एक राज्य है, को शुरू से ही एक विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि कुछ घटनाएं उस समय हुई थीं जब जम्मू और कश्मीर के पूर्व शासक भारतीय संघ में शामिल हुए थे। विधायी योजना से पता चलता है कि विलय के समय मौजूद विशेष शर्तों के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग से निपटा जाना है। [अनुच्छेद 10,11 और 13] [1004-छ-ज ; 1005-क-ख; 1009-ड]

प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1959)

2 एससीआर 270-पर भरोसा किया।

संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1969)

2 एस. सी. आर. 365-निर्दिष्ट।

1.2 जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है जिसके द्वारा वह भारत संघ को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी मामलों में शासित होता है। भारत के संविधान में किए गए संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य पर तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, जम्मू और कश्मीर राज्य पर ऐसे संशोधन लागू करते हैं। संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच शक्तियों का वितरण दर्शाता है कि राष्ट्रीय महत्व के मामले, जिनमें एक समान नीति वांछनीय है, भारत संघ के पास बनाए रखे जाते हैं, और स्थानीय विषय के मामले जम्मू और कश्मीर राज्य के पास रहते हैं। भले ही जम्मू और कश्मीर का संविधान राज्य में जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की स्थापना करता है, फिर भी, भारत के संविधान की व्याख्या करने और संविधान का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई को अमान्य करने का सर्वोच्च प्राधिकरण पूरी तरह से मौजूद पाया गया है। जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय से अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होती है, और कुछ मामूली संशोधनों को हटा दिया जाता है, अनुच्छेद 124 से 147 सभी जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 135 और 139 को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 135 और 139 को हटाने के प्रभाव का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, उस अनुच्छेद 135 में केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 139. सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 (2) में

उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी भारत के नागरिक हैं, और यह कि कोई दोहरी नागरिकता नहीं है जैसा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ अन्य संघीय संविधानों द्वारा माना जाता है। यह सब इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में भी, भारत के संविधान का अर्ध-संघीय ढांचा जारी है, लेकिन उपरोक्त मतभेदों के साथ। [अनुच्छेद 10] [1004-ख-छ]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1964 (1) एससीआर 371-पर निर्भर था।

1.3 अनुच्छेद 370 के उपखंड (1) (घ) के अधीन, भारतीय संविधान के अन्य उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राष्ट्रपति आदेश विनिर्दिष्ट, यदि हो, लागू होंगे। [अनुच्छेद 14] (1009-च)

1.4 यह कहना सही नहीं है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 368 के प्रावधान के तहत एक संवैधानिक संशोधन वास्तव में लागू नहीं होता है, जैसा कि उक्त राज्य में लागू होता है, जब तक कि राज्य सरकार की सहमति न हो और इसलिए, संसदीय विधान को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होने से पहले राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता होगी। एक संवैधानिक संशोधन एक साधारण कानून से गुणवत्ता में अलग होता है और अनुच्छेद 368 के प्रावधान की भाषा और अनुच्छेद 370 की भाषा अलग होती है और इसे उनकी शर्तों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 यह स्पष्ट करता है कि एक बार जब संघ सूची या समवर्ती सूची में से किसी एक मामले को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर राज्य की आगे सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। [अनुच्छेद 15] [1011-च-ज]

1.5 जम्मू और कश्मीर आदेश, 1954 को लागू होने वाला संविधान कुछ संशोधनों और संशोधनों के साथ 20 जून, 1964 को लागू भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को अपनाता है। यह तर्क कि अनुच्छेद 370 (1) (ख) संसद की शक्ति को 'सीमित' करता है, इस तथ्य से उत्तर मिलता है कि भारत का पूरा संविधान, जैसा कि 1964 में मौजूद है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया है, इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 370 (ठ) (ख) और (घ) दोनों का लाभ उठाते हुए। और अभिव्यक्ति 'तक सीमित' अनुच्छेद 370 (1) (घ) में नहीं आती है जिसके तहत यह अपवादों और संशोधनों के अधीन भारत के पूरे संविधान को अपनाने के लिए खुला है। [अनुच्छेद 18] [1013-च-छ]

1.6 1954 के आदेश द्वारा, भारत के संविधान के भाग 11 में, अनुच्छेद 246 में खंड (1) में आने वाले शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "खंड (2) और (3)" के लिए शब्द, कोष्ठक और आकृति: खंड (2) "प्रतिस्थापित किया जाएगा और खंड (2) में आने वाले" खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी "शब्दों, कोष्ठकों और आकृतियों का लोप किया जाएगा और संपूर्ण खंड (3) और (4) का लोप किया जाएगा। समान रूप से, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 248 और प्रविष्टि 97 सूची 1 को संशोधित किया गया है ताकि संसद को केवल तीन विषयों के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति हो- (1) आतंकवादी कृत्यों से जुड़ी गतिविधियों की रोकथाम, (2) भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने या उसे बाधित करने या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से को सौंपने की दिशा में निर्देशित गतिविधियों की रोकथाम, और (3) तीन निर्दिष्ट विषयों पर कर। महत्वपूर्ण रूप से, खंड (च) जिसमें अनुच्छेद 254 को संशोधित रूप में शामिल किया गया था, प्रपत्र आदेश संख्या 66 द्वारा हटा दिया गया था, जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि 1963 के पश्चात्, भारत के संविधान में अपने वर्तमान रूप में अनुच्छेद 254 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होगा। इसी तरह, 7वीं अनुसूची संघ सूची में, प्रविष्टियों की चूक अब केवल चार यानी जो प्रविष्टियाँ 8,9,34 और 79 तक सीमित है, कुछ अन्य प्रविष्टियों को संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूची 1 की प्रविष्टियाँ 45 और 95 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होती हैं। राज्य सूची बनी हुई है, पूरी तरह से हटा दिया गया, और 1963 के बाद से, समवर्ती सूची जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होती है जिसमें कई प्रविष्टियों को हटा दिया गया है। संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित प्रविष्टि 6 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है। प्रविष्टि 6 लागू नहीं होती है क्योंकि इसे राज्य और प्रवेश तक विस्तारित नहीं किया गया है - यह लागू नहीं होता क्योंकि भारत के संविधान में 42वां संशोधन, जिसने समवर्ती सूची में प्रविष्टि 11 को पेश किया था, स्वयं लागू नहीं है। (अनुच्छेद 18,19) (1014-छ; 1015-ग-च)

1.7 भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का संयुक्त पठन, 1954 के राष्ट्रपति के आदेश का यथा संशोधनसमय-समय पर, और जम्मू और कश्मीर का संविधान, 1956 जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य की तुलना में भारत की संसद की विधायी क्षमता का संबंध है, निम्नलिखित स्थिति की ओर ले जाता है:

1. भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 में निहित 1954 के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट सभी प्रविष्टियां उन प्रविष्टियों में निर्धारित विषय मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करेंगी।

2. समान रूप से, अनुच्छेद 248 के साथ पठित प्रविष्टि 97 सूची 1 में निहित अवशिष्ट शक्ति के तहत, निर्दिष्ट विषय-वस्तुएं इंगित करेंगी कि उपर्युक्त विषय-वस्तु से संबंधित अनन्य विधियां अधिनियमित करने की संसद की शक्ति का विस्तार केवल उपरोक्त विषय-वस्तु पर ही होगा और आगे नहीं।

3. भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची III के तहत 1954 के राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट प्रविष्टियों के संबंध में संसद के पास जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ समवर्ती शक्ति होगी। इसका अर्थ यह होगा कि अनुच्छेद 254 पर लागू तिरस्कार के सिद्धांतों पर इस न्यायालय के सभी निर्णय उन कानूनों पर पूरी तरह से लागू होंगे जो इन विषय मामलों से संबंधित हैं।

4. प्रत्येक अन्य विषय जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची I या सूची III में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होता है, जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है। [अनुच्छेद 21] [1016-ड-ज; 1017-क-ख]

1.8 यह कहना सही नहीं है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में मूल रूप से अपनाए गए विषयों को रोक दिया गया था और जब तक अनुच्छेद 370 बना रहता है, तब तक उन्हें कभी भी संसद को प्रत्यायोजित या प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 (1) (ख) के तहत राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि संसद को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए केवल संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विधान के क्षेत्रों पर कानून बनाने की शक्ति होगी। जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाला अनुच्छेद 368, स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में किसी भी संवैधानिक संशोधन को जम्मू और कश्मीर राज्य की सहमति से लागू करने की अनुमति देता है। इसमें एक संशोधन शामिल होगा जो या तो राज्य सूची में जोड़ता है या घटाता है और संसद को विशेष रूप से सूची I के तहत या समवर्ती रूप से सूची III के तहत प्रदान करता है, जो अब तक राज्य सूची में एक विषय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (घ) में आने वाले "संशोधन" शब्द को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और इसमें वे सभी संशोधन शामिल होंगे जो या तो भारत के

संविधान के प्रावधानों को सीमित करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं या विस्तारित करते हैं या विस्तारित करते हैं। इस कारण से यह भी स्पष्ट है कि जब तक अनुच्छेद 370 की कवायद का पालन किया जाता है, तब तक कुछ भी नहीं रोका जा सकता है। [अनुच्छेद 22] [1017-ग-छ]

पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति (1962) 1 एससीआर 688; संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1969) 2 एससीआर 365- पर भरोसा किया गया।

1.9 जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 3, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, एक महत्वपूर्ण घोषणा करती है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और होगा। और यह प्रावधान संशोधन के दायरे से बाहर है। भारत के संविधान के प्रारंभिक अनुच्छेद, अर्थात् "हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए"... को जम्मू और कश्मीर के संविधान में पूरी तरह से हटा दिया गया है। संप्रभुता का कोई संदर्भ नहीं है। न ही अपने लोगों का उल्लेख करते समय "नागरिक" अभिव्यक्ति का कोई उपयोग है। जम्मू और कश्मीर के लोग जिनके लिए संविधान में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग III के तहत "स्थायी निवासी" के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन सबसे ऊपर, जम्मू और कश्मीर का संविधान भारत संघ के साथ राज्य के मौजूदा संबंधों को उसके अभिन्न अंग के रूप में परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के पास भारत के संविधान और अपने स्वयं के संविधान के बाहर संप्रभुता का कोई निशान नहीं है, जो भारत के संविधान के अधीन है। इसलिए इसे इसके निवासियों को एक अलग और विशिष्ट वर्ग के अर्थ में संप्रभु होने के रूप में वर्णित करना पूरी तरह से गलत है। जम्मू और कश्मीर के निवासी भारत के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक हैं। वास्तव में, इसे जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 6 द्वारा मान्यता प्राप्त है। वे पहले भारत के संविधान और जम्मू और कश्मीर के संविधान द्वारा शासित होते हैं। यह जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 10 द्वारा स्पष्ट किया गया है। [अनुच्छेद 41,42 और 43] [1029-ग-घ; 1030-च-ज; 1031-क-ग]

2.1 बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली प्रविष्टि 45 सूची I के अंतर्गत आती है। प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

(सरफेसी) प्रविष्टि 45 सूची 1 से संबंधित है और यह कि राज्य सूची के तहत किए गए किसी भी अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आवेदन के आधार पर को रास्ता देना सरफेसी होगा। [अनुच्छेद 24,27] [1018- ख;1020 -ड]

भारत संघ बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन 2002 (2) एससीआर 450: (2002) 4 एससीसी 275; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य 2009 (3) एससीआर 735: (2009) 4 एससीसी 94; यूको बैंक और अन्य बनाम दीपक देबबर्मा और अन्य 2016 (11) जेटी 251:2016 (12) स्केल 301; आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ 1970 (3) एससीआर 530: (1970) 1 एससीसी 248-पर निर्भर था।

कनाडा के लिए महान्यायवादी बनाम क्यूबेक प्रांत के लिए महान्यायवादी, 1947 अपील मामले 33- निर्दिष्ट।

2.2 चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 जम्मू और कश्मीर राज्य में क्रियाशील नहीं है, इसलिए उक्त सूची में कोई प्रतिस्पर्धी प्रविष्टि नहीं है और इसलिए यह निष्कर्ष निकालता है कि सूची 1 की प्रविष्टि 45 और 95 को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। [अनुच्छेद 30] (1022-क-ख)

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम एमएस फारूकी 1972 (3) एससीआर 881: (1972) 1 एससीसी 872- पर निर्भर था।

भारत संघ बनाम एच. एस. ढिल्लों 1972 (2) एस.सी.आर. 33- निर्दिष्ट।

2.3 सरफेसी को सार और तत्व के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि सार और तत्व में संपूर्ण अधिनियम प्रविष्टि 45 सूची 1 के लिए संदर्भित है जिसे प्रविष्टि 95 सूची 1 के साथ पढ़ा जाता है जिसमें यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से, और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। सरफेसी "संपत्ति के हस्तांतरण" से संबंधित नहीं है। [अनुच्छेद 32] (1023-छ-ज; 1024-क)

2.4 सरफेसी की धारा 13 (4) के अधीन, उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने और उनके ऋणों की प्राप्ति के लिए उन्हें सौंपने या बेचने के अलावा, बैंक उधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन भी कर सकते हैं, और/या किसी व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं ताकि सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया जा सके, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया है। सुरक्षित लेनदार के रूप में बैंक किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा, किसी भी व्यक्ति से, जिसने उधारकर्ता से किसी भी सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण किया है और जिससे पैसा उधारकर्ता को देय या देय है, सुरक्षित लेनदार को इतना पैसा देने की आवश्यकता कर सकते हैं जितना कि सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिक्री या समनुदेशन के माध्यम से संपत्ति का अंतरण, बैंक को देय सुरक्षित ऋण की वसूली के कई उपायों में से केवल एक है और यह मामला होने पर, यह स्पष्ट है कि सरफेसी को, समग्र रूप से, संभवतः सार और तत्व में नहीं कहा जा सकता है, एक अधिनियम जो विषय वस्तु "संपत्ति के अंतरण" से संबंधित है। [अनुच्छेद 32] [1024-ख-घ]

2.5 सरफेसी की धारा 17क और धारा 18ख, जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होती हैं, क्रमशः 'ऋण वसूली अधिकरण' और 'अपीलीय अधिकरण' के स्थान पर 'जिला न्यायाधीश' और 'उच्च न्यायालय' को प्रतिस्थापित करती हैं। यह स्पष्ट होगा कि ये प्रावधान प्रविष्टि 45 के लिए बैंकिंग के सहायक होने के रूप में संदर्भित हैं, और स्पष्ट रूप से प्रविष्टि 95 सूची 1 के लिए, क्योंकि इन प्रावधानों द्वारा बैंकों को देय ऋणों की वसूली के विशेष विषय के लिए न्यायालयों की अधिकारिता और शक्ति निर्धारित की गई है। समग्र रूप से सरफेसी सूची 1 की प्रविष्टियों 45 और 95 के लिए संदर्भित होगा। पहले किसी अधिनियम को विभिन्न भागों में विभाजित करना और फिर उन भागों को विधायी सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए संदर्भित करना सही नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि धारा 17क और 18ख सहित संपूर्ण अधिनियम सूची 1 की प्रविष्टियां 45 और 95 के लिए निर्दिष्ट होगा और इसलिए समग्र रूप से यह अधिनियम अनिवार्य रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्य करेगा। [अनुच्छेद 32,33 और 37] [1024-डी; 1025-घ; 1027-ख]

महाराष्ट्र राज्य बनाम नरोत्तमदास जेठाबाई (1950) 1 एससीआर 51; जमशेद एन. गुजदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 (1) SCR 223: (2005) 2 SCC 591; ए. एस. कृष्णा और अन्य बनाम मद्रास राज्य 1957 SCR 399- पर भरोसा किया।

2.6 समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11क के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय पूर्णतः गलत है। यह प्रविष्टि जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित नहीं है। "न्याय प्रशासन" तभी लागू होगा जब सूची 1 की प्रविष्टियाँ 45 और 95 आकर्षित नहीं होंगी। भले ही ऐसा न हो, "न्याय का प्रशासन" अभिव्यक्ति सामान्य है और इसे उन विशेष कानूनों को रास्ता देना चाहिए जो प्रविष्टि 95 सूची 1 के तहत अधिनियमित हैं, जब उसी सूची में एक और प्रविष्टि के साथ जोड़ा जाता है-इस मामले में प्रविष्टि 45 सूची 1। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) में यह स्पष्ट किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 का राज्य के भीतर होने वाली नीलामी बिक्री में सम्मान किया जाएगा। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि सरफेसी के किसी भी प्रावधान के साथ कोई टकराव या प्रतिकूलता नहीं है। [अनुच्छेद 38,39 और 40] [1027-ग-ड; 1028-ग ग,ड]

2.7 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि का उल्लेख करना और यह कहना पूरी तरह से गलत है कि चूंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तारित नहीं है, इसलिए संसद को सरफेसी की धारा 17क और 18ख को अधिनियमित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं होगी। इस निष्कर्ष में कम से कम तीन त्रुटियाँ हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफेसी के प्रावधानों को विच्छेदित करना और उन्हें विभिन्न सूचियों के तहत विभिन्न प्रविष्टियों से संलग्न करना संभव नहीं है। सम्पूर्ण सरफेसी सूची 1 की प्रविष्टि 45 और सूची 1 की प्रविष्टि 95 के लिए संदर्भित है। दूसरा, आक्षेपित निर्णय से जो छूट गया है वह यह है कि प्रविष्टि 95 सूची 1, सरफेसी में निहित मामलों के संबंध में क्रमशः जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय को शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए संसद के लिए विधायी शक्ति का एक स्रोत है। और तीसरा, विषय "न्याय प्रशासन" केवल सामान्य है और इसे केवल तभी संदर्भित किया जा सकता है जब प्रविष्टि 95 सूची 1 प्रविष्टि 45 सूची 1 के साथ पढ़ा जाता है आकर्षित नहीं होता है। भले ही यह पाया जाता है कि जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 केवल कुछ व्यक्तियों को जम्मू और कश्मीर राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार देती है, फिर भी, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) प्रावधान जो इस प्रावधान को मान्यता देता है, को दरकिनार कर दिया गया है। किसी भी मामले में पहले जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 को सरफेसी के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा सामंजस्य असंभव है, तो यह स्पष्ट है

कि जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के आधार पर, जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 को सरफेसी को रास्ता देना होगा, न कि इसके विपरीत। [अनुच्छेद 44] [1032-ख-छ]

महाराष्ट्र राज्य बनाम नरोत्तमदास जेठाबाई (1950) 1 एससीआर 51; जमशेद एन. गुजदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 (1) एससीआर 223: (2005) 2 एससीसी 591- पर निर्भर था।

2.8 उच्च न्यायालय का यह कथन गलत है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 5 के संदर्भ में, राज्य को अपने स्थायी निवासियों के अधिकारों को उनकी अचल संपत्तियों से संबंधित विधियों के संबंध में विधान बनाने की पूर्ण संप्रभु शक्ति है। उच्च न्यायालय का यह कहना भी गलत है कि राज्य विधायिका ने जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 को अधिनियमित किया है, इसलिए, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के विषय/नागरिक उक्त प्रावधान के आधार पर संरक्षित हैं, सरफेसी इस तरह के संरक्षण में घुसपैठ और बाधा नहीं डाल सकता है। सूची I की प्रविष्टियाँ 45 और 95 संसद को बैंकिंग के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है, और संपूर्ण सरफेसी को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची I प्रविष्टि 45 और 95 के लिए संदर्भित कहा जा सकता है। इस मामले में, जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 केवल उन क्षेत्रों में काम करेगी जिनमें संसद के पास राज्य के लिए कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर कानून के माध्यम से सरफेसी के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अनिवार्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर उक्त कानून को रास्ता देना चाहिए, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 5 के साथ पढ़ा जाता है। इस प्रकार, धारा 13 (1) और (4) को संसद की विधायी क्षमता से परे नहीं ठहराया जा सकता है। [अनुच्छेद 40] (1028-छ-झ; 1029-क-ख)

3. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सरफेसी के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता है, यह कहने के संदर्भ में एक विरोधाभास है कि सरफेसी का लाभ उन बैंकों द्वारा उठाया जा सकता है जो जम्मू और कश्मीर राज्य से उत्पन्न होते हैं, जो धन प्राप्त करने के लिए उनके बकाया हैं और जो उधारकर्ताओं के लिए अग्रिम किए गए हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी नहीं हैं। [अनुच्छेद 47] (1034-ग,घ)

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

1964 (1) एस.सी.आर 371	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 8
(1959) पूरक 2 एस.सी.आर 270	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 11
(1969) 2 एस.सी.आर 365	संदर्भित	अनुच्छेद 12
(1962) 1 एस.सी.आर 688	संदर्भित	अनुच्छेद 14
2002 (2) एस.सी.आर 450	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 24
2009 (3) एस.सी.आर 735	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 25.
2016 (12) स्केल 301	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 26
1970 (3) एस.सी.आर 530	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 28
1947 अपील मामले 33	संदर्भित	अनुच्छेद 29
1972 (2) एस.सी.आर 33	संदर्भित	अनुच्छेद 30
1972 (3) एस.सी.आर. 881	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 31
(1950) 1 एस.सी.आर. 51	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 34
2005 1 एस.सी.आर. 223	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 36
1957 एस.सी.आर. 399	भरोसा किया गया	अनुच्छेद 37

सिविल अपीलीय क्षेत्रियाधिकर: सिविल अपीलीय संख्या 12237-12238/2016

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू के निर्णय और आदेश दिनांक 16.07.2015 में ओडब्ल्यूपी संख्या 1031/2004 और 1539/2012

साथ

सी. ए. संख्याएं 12240-12246/2016

राकेशद्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कपूर, अनमोल चंदन, सुश्री प्रियंका दास, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री संस्कृति पाठक, केशव ठाकुर, राजेश चौहान, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

विजय हंसारिया, भारत भूषण प्रसून वरिष्ठ अधिवक्ता, तुषार जॉन, अवनीश पांडे, सुश्री सोनम प्रिया, सुश्री स्नेहा कलीता, रवि कुमार तोमर, सुनील फर्नांडीस, सुश्री मिट्टू जैन, अर्नव विद्यार्थी, अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था।

आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति। अनुमति दी गई।

1. भारत का संविधान दुनिया भर के राष्ट्रों के अनुभव से लिया गया एक पच्चीकारी है। इस संविधान की संघीय संरचना काफी हद तक भाग 11 में परिलक्षित होती है जो काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है। जम्मू और कश्मीर राज्य इस संघीय ढांचे का एक हिस्सा है। ऐतिहासिक कारणों से, यह एक ऐसा राज्य है जिसे भारत के संविधान के ढांचे के भीतर विशेष सम्मान दिया जाता है। यह मामला जम्मू और कश्मीर राज्य और भारत संघ की तुलना से संबंधित है, जहाँ तक दोनों के बीच विधायी संबंधों का संबंध है।

2. वर्तमान अपीलें जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा दिनांक 16.7.2015 को पारित एक निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिभूतिकरण के विभिन्न प्रमुख प्रावधान हैं। और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद "सरफेसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) संसद की विधायी क्षमता से बाहर थे, क्योंकि वे जम्मू और कश्मीर के संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1920 की धारा 140 से टकराएंगे। उक्त अधिनियम को भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंकों पर लागू नहीं माना गया है जो अखिल भारतीय बैंक हैं।

3. मामले के गुण-दोष में जाने से पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरफेसी एक ऐसा अधिनियम है जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को न्यायालय की प्रक्रिया के बाहर अपने प्रतिभूति हित को लागू करने का अधिकार देता है-इसकी धारा 13 के तहत उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने और उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया के बाहर बेचने का अधिकार देता है। धारा 13 (1) और (4) और 17 वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक सरफेसी के प्रमुख प्रावधान हैं और यहां निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

“धारा 13. सुरक्षा हित का प्रवर्तन।

(1) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (4/1882) की धारा 69 या धारा 69क में किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित कोई प्रतिभूति हित, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे लेनदार द्वारा न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना लागू किया गया।

(4) यदि उधारकर्ता निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करने में विफल

रहता है तो उप धारा (2) सुरक्षित लेनदार अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक का सहारा ले सकता है, अर्थात्:-(क) सुरक्षित संपत्ति की प्राप्ति के लिए पट्टे, हस्तांतरण या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेना; (ख) सुरक्षित संपत्ति की प्राप्ति के लिए पट्टे, हस्तांतरण या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित उधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेना:

बशर्ते कि पट्टे, हस्तांतरण या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार होगा। इसका प्रयोग केवल वहां किया जाता है जहां उधारकर्ता के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा ऋण की प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है:

आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां पूरे व्यवसाय या व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन अलग करने योग्य है, वहां सुरक्षित लेनदार उधारकर्ता के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा जो ऋण की प्रतिभूति से संबंधित है। (ग) ऐसी सुरक्षित आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् प्रबंधक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को नियुक्त करेगा, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है; (घ) किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने उधारकर्ता से कोई सुरक्षित संपत्ति अर्जित की है और जिससे कोई धन देय है या जो उधारकर्ता का देय हो सकता है, सुरक्षित लेनदार को इतना धन देने की अपेक्षा करेगा, जितना कि सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।

XXX

धारा 17 अपील करने का अधिकार।

(1) इस अध्याय के अधीन प्रतिभूत लेनदार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट उपायों में से किसी से व्यथित कोई व्यक्ति (उधारकर्ता सहित), उस तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, जिस दिन ऐसा उपाय किया गया था, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले ऋण वसूली अधिकरण को विहित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा:

बशर्ते कि उधारकर्ता और उधारकर्ता से भिन्न व्यक्ति द्वारा आवेदन करने के लिए भिन्न-भिन्न फीस विहित की जाएं।

स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए, इसे एतद्वारा घोषित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार द्वारा उधारकर्ता को उसके अभ्यावेदन या आपत्ति को स्वीकार न करने के कारणों का संप्रेषण या उधारकर्ता को कारणों के संप्रेषण के स्तर पर सुरक्षित लेनदार की संभावित कार्रवाई व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) को इस उप-धारा के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण को आवेदन करने का हकदार नहीं बनाएगी।

(2) ऋण वसूली अधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार हैं।

(3) यदि ऋण वसूली अधिकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई उपाय, जो प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए गए हैं, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं हैं और उनसे उधारकर्ता को व्यवसाय के प्रबंधन की बहाली या प्रतिभूत आस्तियों के कब्जे की बहाली की अपेक्षा की जाती है, तो वह आदेश द्वारा, प्रतिभूत लेनदारों द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी या अधिक उपायों को अमान्य घोषित कर सकता है और उधारकर्ता को प्रतिभूत आस्तियों के कब्जे को बहाल कर सकता है या यथास्थिति, उधारकर्ता को व्यवसाय के प्रबंधन को बहाल कर सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूत लेनदार के संबंध में उचित समझे।

(4) यदि ऋण वसूली अधिकरण यह घोषित करता है कि धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया उपाय इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रतिभूत लेनदार को अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट उपायों में से एक या अधिक का सहारा लेने का अधिकार दिया जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी भी आवेदन पर ऋण वसूली अधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और ऐसे आवेदन की तारीख से साठ दिनों के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा: बशर्ते कि ऋण वसूली अधिकरण समय-समय पर लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए उक्त अवधि बढ़ा सकता है,

तथापि, यह कि ऋण वसूली अधिकरण के पास ऐसे आवेदन के लंबित रहने की कुल अवधि, उपधारा (1) के अधीन किए गए ऐसे आवेदन की तारीख से चार मास से अधिक नहीं होगी।

(6) यदि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट चार मास की अवधि के भीतर आवेदन का निपटान नहीं किया जाता है तो आवेदन का कोई भी पक्षकार ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष लंबित आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए ऋण वसूली अधिकरण को निर्देश देने के लिए अपीलीय अधिकरण को ऐसे प्रपत्र में आवेदन कर सकता है जो विहित किया जाए और अपीलीय अधिकरण ऐसे आवेदन पर ऋण वसूली अधिकरण द्वारा लंबित आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए आदेश दे सकता है।

(7) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध किए गए को छोड़कर, ऋण वसूली अधिकरण, जहां तक हो सके, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवेदन का निपटान करेगा।

4. धारा 34 घोषित करती है कि सिविल न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारित करने के लिए सशक्त है, और धारा 35 एक सामान्य गैर-अस्थिर खंड है, यह घोषणा करते हुए कि यह अधिनियम प्रभावी होगा, किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद फिलहाल लागू है।

5. वर्तमान अपीलों में विवाद की जड़ यह है कि क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में अपने आवेदन में सरफेसी को संसद की विधायी क्षमता के भीतर माना जाएगा। इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए, हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी से व्यापक दलीलें सुनी हैं। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसे जम्मू और कश्मीर संविधान, 1956 की धारा 5 के साथ पढ़ा जाता है। यह उनका निवेदन है कि जम्मू और कश्मीर के विलय का दस्तावेज, 1947 स्वयं यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 7वीं अनुसूची की सूची 1 लागू होगी, और यह कि विभिन्न संविधान, अनुच्छेद 370 के तहत समय-समय पर जारी जम्मू और कश्मीर के आदेशों पर लागू होने से यह स्पष्ट होता है कि प्रविष्टि 45 और 95 सूची 1 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (1) संसद को सरफेसी को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करेगा। वास्तव में,

उनके अनुसार, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय भी इसे स्वीकार करता है। उनके अनुसार, एक बार प्रविष्टि 45 सूची I की कोई अन्य प्रतिस्पर्धी प्रविष्टि नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं किया गया है, और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची III में निहित न्याय प्रशासन से संबंधित प्रविष्टि 11क जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होती है, और संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित प्रविष्टि 6 सूची III भी लागू नहीं होती है-यह उनका मामला है कि प्रविष्टि 45 सूची I को पूरी तरह से पढ़ा जाना है और किसी अन्य प्रविष्टि के प्रावधानों द्वारा काटा नहीं जाता है। यदि यह पाया जाता है कि संपूर्ण सरफेसी वास्तव में सूची I की 95 के साथ पठित प्रविष्टि 45 के तहत अधिनियमित है, तो यह स्पष्ट होगा कि किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार और तथ्य में अधिनियम इन दो प्रविष्टियों के लिए संदर्भित होगा। इस मामले में, राज्य की विधायी शक्ति केवल तभी आती है जब सूची I या III की प्रविष्टियों में से कोई भी आकर्षित नहीं होती है। प्रविष्टि 11क और प्रविष्टि 6 का उल्लेख करना और आगे यह कहना कि जम्मू और कश्मीर के संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 140, सरफेसी के प्रमुख प्रावधानों को विधायी क्षमता के बिना प्रदान करेगी, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह दिखाने के लिए कई निर्णयों का उल्लेख किया कि ऋणों की वसूली बैंकिंग व्यवसाय का उतना ही हिस्सा है जितना कि ऋण देना, और इसलिए 2002 का पूरा अधिनियम प्रविष्टि 95 सूची I के साथ पठित प्रविष्टि 45 के अंतर्गत आएगा। उनके अनुसार, इसलिए, विवादित निर्णय कई बुनियादी बातों पर गलत है और इसे दरकिनार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कई अन्य निर्णयों का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया जिन पर हम इस निर्णय के दौरान विचार करेंगे।

6. निजी प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया ने तर्क दिया है कि चूंकि भारत का संविधान और जम्मू-कश्मीर का संविधान दोनों लोगों की संप्रभु इच्छा की अभिव्यक्ति हैं, इसलिए उनका समान दर्जा है और कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। अपीलार्थियों की दलीलों को पूरा करने के लिए उनका मूल तर्क यह है कि सरफेसी अधिनियम, सार और तथ्य में, "संपत्ति के हस्तांतरण" से संबंधित है न कि "बैंकिंग" से और इसलिए, यह संसद की क्षमता से बाहर और विशेष रूप से राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर होना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 (1)(ख) के तहत संसद की शक्ति "सीमित" है, जबकि जम्मू और कश्मीर के संविधान के तहत, राज्य विधानमंडल के पास सभी मामलों पर पूर्ण शक्तियां हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारत के संविधान

के तहत 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों को निष्क्रिय कर दिया गया है और जब तक अनुच्छेद 370 बना रहता है, तब तक उन्हें कभी भी संसद में प्रत्यायोजित या गैर-निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है और इसलिए समवर्ती सूची के अधीन राज्य सूची का कोई भी हस्तांतरण बाद में जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से संसद को शक्ति प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन हर बार जब संसद ऐसी शक्ति के तहत कानून बनाती है, इससे पहले कि ऐसा कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में काम कर सके, राज्य सरकार की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। यह भी कहा गया था कि भारत के संविधान में किया गया संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य इसे जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए सहमत नहीं होता है, इस मामले में इस तरह के संशोधन को लागू करने वाला राष्ट्रपति का आदेश ही प्रभावी होगा। इसके अलावा, उनके अनुसार, जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के साथ सीधे टकराव में है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम प्रबल होना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 17क और 18ख, न्याय के प्रशासन से संबंधित धाराएं हैं, जो विशुद्ध रूप से एक राज्य का विषय है, यह भी संसद के अधिकार से बाहर होगा। उन्होंने अनुच्छेद 35क पर भरोसा किया और इस संबंध में विवादित निर्णय का समर्थन किया, और आगे कहा कि अपीलार्थियों की ओर से उद्धृत विभिन्न निर्णय अलग-अलग थे क्योंकि वर्तमान मामले में तथ्य की स्थिति उन निर्णयों की स्थिति से पूरी तरह से अलग थी।

7. जम्मू और कश्मीर राज्य के विद्वान स्थायी वकील श्री सुनील फर्नांडीस ने अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर के संविधान का कुछ विस्तार से उल्लेख किया और इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने स्थानीय वैधानिक कानूनों की ओर भी इशारा किया जो राज्य के निवासियों से संबंधित भूमि को गैर-राज्य के निवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाते हैं। उनका निवेदन था कि यद्यपि सरफेसी अधिनियम संसद द्वारा प्रविष्टि 45 सूची 1 के आधार पर अधिनियमित किया गया था, फिर भी अकेले धारा 13 (4) संयोग से जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों के संपत्ति अधिकारों का अतिक्रमण करती है और इसे पढ़ा जाना चाहिए ताकि इस धारा के तहत राज्य के स्थायी निवासी की संपत्ति को ऐसे व्यक्ति को बेचने की अनुमति नहीं होगी जो राज्य का स्थायी निवासी नहीं है। उनका आगे यह निवेदन था कि सरफेसी नियमों के नियम 8 (5) में जोड़े गए प्रावधान को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा पढ़ा जाता है तो जम्मू और कश्मीर राज्य को सरफेसी पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ**, 1 964 (1) एस.सी.आर. 371 एक स्पष्ट निर्णय में, मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने बहुमत के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत संघ के प्रति एक मजबूत झुकाव के साथ अर्ध-संघीय है, जो इस प्रकार है:-

"(क) सरकार का एक सही मायने में संघीय रूप स्वतंत्र और संप्रभु इकाइयों के बीच एक सुसम्बद्ध या समझौते की परिकल्पना करता है ताकि वे अपने सामान्य हित में आंशिक रूप से अपना अधिकार सौंप सकें और इसे एक संघ में निहित कर सकें और घटक इकाइयों में अधिकार के अवशेष को बनाए रख सकें। आम तौर पर प्रत्येक घटक इकाई का अपना अलग संविधान होता है जिसके द्वारा यह संघ को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी मामलों में शासित होता है, और संघ का संविधान मुख्य रूप से इकाइयों के प्रशासन पर काम करता है। हमारा संविधान इस तरह के किसी समझौते या समझौते का परिणाम नहीं था: एक एकात्मक राज्य का गठन करने वाली इकाइयाँ जो गैर-संप्रभु थीं, उन्हें सत्ता के त्याग से संघ में बदल दिया गया था

(ख) संविधान की सर्वोच्चता जिसे घटक इकाइयों को छोड़कर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान निस्संदेह सर्वोच्च है लेकिन इसे अकेले केंद्रीय संसद द्वारा बदला जा सकता है और इकाइयों के पास इसे बदलने की कोई शक्ति नहीं है।

(ग) संघ और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण प्रत्येक अपने क्षेत्र में दूसरे से समन्वय और स्वतंत्र होता है। शक्ति के इस तरह के वितरण का आधार यह है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जिनमें इकाइयों के हित में एक समान नीति वांछनीय है, प्राधिकरण संघ को सौंपा जाता है, और स्थानीय चिंता के मामले राज्य के पास रहते हैं।

(घ) संविधान की व्याख्या करने और संविधान का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई को अमान्य करने का न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकार। एक संघीय संविधान, अपनी प्रकृति से, नियंत्रण और संतुलन से बना होता है और इसमें संघ के कार्यकारी और विधायी प्राधिकरण और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए प्रावधान होने चाहिए। [पृष्ठ 396-397 पर]

9. यह पाया गया कि जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा अन्य राज्यों का संबंध है, इंडिका (क) और (ख) अनुपस्थित थे जबकि इंडिका (ग) और (घ) मौजूद थे, और इससे

संविधान के विभिन्न अन्य अनुच्छेदों के पठन के साथ इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह निर्णय लेने के लिए नेतृत्व किया कि संविधान का संघीय ढांचा केंद्रीय विधानमंडल और केंद्र सरकार की ओर दृढ़ता से झुकता है।

10. जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य का संबंध है, यह स्पष्ट है कि इंडिका (ख) अनुपस्थित है। जहाँ तक अन्य संकेतकों का संबंध है, राज्य का अपना अलग संविधान है जिसके द्वारा यह भारत संघ को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी मामलों में शासित होता है। भारत के संविधान में किए गए संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य पर तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, जम्मू और कश्मीर राज्य पर ऐसे संशोधन लागू करते हैं। संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच शक्तियों का वितरण दर्शाता है कि राष्ट्रीय महत्व के मामले, जिनमें एक समान नीति वांछनीय है, भारत संघ के पास बने रहते हैं और स्थानीय चिंता के मामले जम्मू और कश्मीर राज्य के पास बने रहते हैं। और, भले ही जम्मू और कश्मीर का संविधान राज्य में जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की स्थापना करता है, फिर भी, भारत के संविधान की व्याख्या करने और संविधान का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई को अमान्य करने के लिए न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकार पूरी तरह से मौजूद पाया गया है। जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय से अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में होती है, और कुछ मामूली संशोधनों को हटा दिया जाता है, अनुच्छेद 124 से 147 सभी जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 135 और 139 को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 135 और 139 को हटाने के प्रभाव का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जिसमें अनुच्छेद 135 केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी भारत के नागरिक हैं, और कोई दोहरी नागरिकता नहीं है जैसा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ अन्य संघीय संविधानों द्वारा विचार किया गया है। यह सब हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में भी, भारत के संविधान का अर्ध-संघीय ढांचा जारी है, लेकिन उपरोक्त मतभेदों के साथ। इसलिए श्री हंसारिया के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि भारत के संविधान और जम्मू-कश्मीर के संविधान को समान दर्जा प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।

11. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जम्मू और कश्मीर राज्य, हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अर्थ के भीतर एक राज्य है, को शुरू से ही एक विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि कुछ घटनाएं उस समय हुई थीं जब जम्मू और कश्मीर के पूर्व शासक भारतीय संघ में शामिल हुए थे। इन घटनाओं को **प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1959)** पूरक 2 एससीआर 270 में विस्तार से बताया गया है, जिस पर हम आगे संदर्भ में जाएंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष प्रावधान, अर्थात् अनुच्छेद 370 द्वारा निपटाया जाता है। इस बिंदु पर, इस लेख को निम्नानुसार निर्धारित करना आवश्यक है: -

अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान।

(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 238 के उपबंध लागू नहीं होंगे;

(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति

(i) संघ सूची और समवर्ती सूची के वे मामले, जो राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भारत अधिराज्य के राज्य के परिग्रहण को शासित करने वाले परिग्रहण लिखत में विनिर्दिष्ट मामलों के अनुरूप घोषित किए गए हैं, जिन मामलों के संबंध में अधिराज्य विधानमंडल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है; और

(ii) उक्त सूची में ऐसे अन्य मामले, जैसे राज्य सरकार की सहमति से, राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार का अर्थ है उस समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो महाराजा की उद्घोषणा दिनांक 5 मार्च, 1948 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है;

(ग) अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के प्रावधान उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के ऐसे अन्य प्रावधान उस राज्य के संबंध में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) के अनुच्छेद (i) में निर्दिष्ट राज्य के विलय लिखत में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित हो, राज्य सरकार के परामर्श के अलावा जारी किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश जो पूर्ववर्ती में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित हो, सरकार की सहमति से जारी किया जाए।

(2) यदि खंड (1) के उपखंड (ख) के अनुच्छेद (ii) में या उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट राज्य सरकार की सहमति संविधान सभा के समक्ष राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए बुलाई जाती है, तो उसे ऐसे विनिश्चय के लिए ऐसी सभा के समक्ष रखा जाएगा जो वह उस पर ले सके।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद केवल ऐसे अपवादों और उपांतरणों के साथ और ऐसी तारीख से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, अप्रचलित नहीं रहेगा या अप्रचलित रहेगा: बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

12. अनुच्छेद 370 में पहली बात यह है कि सीमांत नोट में कहा गया है कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी प्रावधान है। हालांकि, अनुच्छेद 369 के विपरीत, जो इस संविधान के प्रारंभ से पांच साल तक के समय में सीमित एक अस्थायी प्रावधान भी है, अनुच्छेद 370 में ऐसी कोई सीमा नहीं पाई जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि इसे अस्थायी प्रकृति का बताया गया है, अनुच्छेद 370 का उपखंड (3) यह स्पष्ट करता है कि यह अनुच्छेद केवल उस तारीख से लागू नहीं होगा जिसे राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करे। और यह अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधान के तहत तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए राज्य की संविधान सभा की सिफारिश न हो। यह हमें इस न्यायालय के एक दिलचस्प निर्णय पर ले जाता है, जिसका नाम है, **संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य**, (1969) 2 एस. सी. आर. 365। इस मामले में, अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता की नजरबंदी को चुनौती दी गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 370 में केवल अस्थायी प्रावधान हैं जो राज्य की संविधान सभा द्वारा राज्य के लिए संविधान तैयार करके अपना काम पूरा करने के बाद प्रभावी नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता की नजरबंदी को सलाहकार बोर्ड का उल्लेख किए बिना जारी

रखा गया था क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 35 (ग) ने जम्मू और कश्मीर में निवारक नजरबंदी से संबंधित किसी भी कानून को संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अयोग्यता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे शुरू में पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जिसे बाद में दस साल और पंद्रह साल तक बढ़ा दिया गया था। ये विस्तार चुनौती का विषय थे, और यह तर्क दिया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति के आधार पर राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग राज्य की संविधान सभा के विघटन से पहले अनुच्छेद 370 के तहत किया जाना चाहिए, और यह कि ऐसी शक्ति को संविधान सभा के विघटन के बाद अस्तित्व में नहीं रखा जाना चाहिए। संविधान पीठ ने तीन कारण बताते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह कहा गया था कि इस अनुच्छेद का कारण यह था कि भारतीय संविधान को लागू करने में समय-समय पर अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सशक्त बनाना आवश्यक था। ऐसा होने पर, अनुच्छेद 370 को आवश्यक रूप से हर बार लागू करना होगा जब राष्ट्रपति, राज्य की सहमति से, यह आवश्यक महसूस करते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन जम्मू और कश्मीर पर लागू किया जाए, अनुच्छेद 368 के विशेष प्रावधान को देखते हुए जो केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद उपखंड (3) के अधीन तभी कार्य करना बंद कर देगा जब राज्य की संविधान सभा द्वारा इस आशय की सिफारिश की जाए। यह पाया गया कि वास्तव में राज्य की संविधान सभा ने एक सिफारिश की थी कि अनुच्छेद को अनुच्छेद के खंड (1) के स्पष्टीकरण में शामिल किए जाने वाले एक संशोधन के साथ लागू किया जाना चाहिए, अर्थात्, जम्मू और कश्मीर के महाराजा को "जम्मू और कश्मीर का सदर-रियासत" अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 370 (2) किसी भी तरह से यह नहीं कहता है कि उक्त अनुच्छेद संविधान सभा के कार्य के पूरा होने या इसके विघटन पर समाप्त हो जाएगा। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि सीमांत नोट अनुच्छेद 370 को केवल एक अस्थायी प्रावधान के रूप में संदर्भित करता है, यह वास्तव में वर्तमान उपयोग में है और उक्त अनुच्छेद के उपखंड (3) में निर्दिष्ट घटना होने तक लागू रहेगा। **समपत प्रकाश** निर्णय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 भी लागू थी ताकि इस अनुच्छेद के अधीन शक्ति का उपयोग समय-समय पर विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जा सके।

13. अनुच्छेद 370 एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है जिसमें कहा गया है कि संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उप-खंड (1) (क) अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। तब से अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया है और आज इसका कोई महत्व नहीं है। इसने केवल पहली अनुसूची के भाग ख में राज्यों के लिए भाग VI के प्रावधानों को लागू करने का उल्लेख किया। चूंकि अनुच्छेद 370 की योजना अलग थी, इसलिए उक्त अनुच्छेद को लागू नहीं करने के लिए कहा गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति उपखंड (ख) (i) में भारत के संविधान की संघ सूची और 7वीं अनुसूची की अंतिम सूची के मामलों तक सीमित होगी, राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप घोषित किया जाता है। यदि उक्त सूची में विलय के दस्तावेज के बाहर उक्त संविधान में निहित अन्य मामलों का विस्तार किया जाना है, तो उन्हें केवल राज्य की सहमति से ही बढ़ाया जा सकता है। ऊपर **प्रेम नाथ कौल** के मामले में परामर्श और सहमति के बीच के अंतर को उजागर किया गया था। इस स्तर पर, इस मामले को कुछ विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक है क्योंकि यह अनुच्छेद 370 के विधायी इतिहास और उक्त अनुच्छेद के तहत किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में जाता है। हम यहां सीधे तौर पर जम्मू और कश्मीर की बड़ी जागीरों के उन्मूलन का अधिनियम, 1950 से संबंधित नहीं हैं, जिसकी वैधता को उक्त निर्णय में चुनौती दी गई। निर्णय में बहुत विस्तार से बताया गया है कि महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत संघ में विलय का दस्तावेज कैसे बनाया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्ता की बागडोर उनके पुत्र युवराज करण सिंह को दिनांक 20.6.1949 की उद्घोषणा द्वारा सौंप दी गई थी, युवराज करण सिंह ने दिनांक 25.11.1949 की उद्घोषणा द्वारा कहा कि भारत का संविधान, जिसे अभी प्रख्यापित किया जाना था, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होगा। इसके अलावा, दिनांक 20.4.1951 की उद्घोषणा द्वारा, वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जानी थी ताकि यह सभा राज्य को अपना संविधान दे सके। इसके बाद निर्णय 1950 के जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति के आदेश और उसके संशोधनों को संदर्भित करता है, जिसे तब 1954 के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके बाद यह कहा जाता है कि, जबकि 370 के उपखंड (1) (ख) (i) में केवल राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है, उपखंड (ii) में सहमति की आवश्यकता होती है, जो योजना भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों के विस्तार या संशोधन के संबंध में उक्त अनुच्छेद के उपखंड (घ) के तहत भी लागू होती है। उपखंड के तहत (घ) संविधान के इतर प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू करने के लिए अभिनिर्धारित किया जा सकता है। यदि विलय के दस्तावेज में

निर्दिष्ट मामलों को लागू किया जाना है, तो केवल राज्य सरकार के साथ परामर्श किया जाता है, और यदि नहीं, तो सहमति होनी चाहिए। अतः अनुच्छेद 370 (1) की योजना स्पष्ट है। चूंकि विलय का दस्तावेज जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती शासक और भारत संघ के बीच एक समझौता है, इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए, इस मामले में यदि कोई मामला पहले से ही प्रदान किया गया है, तो यह बिना अधिक के सीधे लागू हो जाएगा, और भारत के संविधान के अनुरूप भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के विस्तार के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए राज्य सरकार के साथ केवल परामर्श आवश्यक है। तथापि, जब भारत के संविधान के उपबंधों को लागू करने की बात आती है, जो विलय के लिखत में इस प्रकार प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार की सहमति के बिना इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें केवल तभी लागू किया जा सकता है जब राज्य सरकार स्वीकार करती है कि उन्हें इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 (2) के तहत संविधान सभा के समक्ष दी गई राज्य सरकार की सहमति को तभी प्रभावी किया जा सकता है जब संविधान सभा द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। इसलिए यह विधायी योजना दर्शाती है कि विलय के समय मौजूद विशेष शर्तों के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग से निपटा जाना है।

14. अनुच्छेद 370 के उपखंड (1) (घ) के तहत, भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में ऐसे अपवादों और संशोधनों पर लागू होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। **पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति**, (1962) 1 एस.सी. आर. 688 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपखंड (घ) में "संशोधन" एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें परिवर्तन के माध्यम से संशोधन शामिल है। इस न्यायालय ने कहा:

"दिल्ली विधि अधिनियम मामले (1) में विचार के लिए जो प्रश्न आया था, वह अधीनस्थ विधान बनाने में अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजन की शक्ति के संबंध में था। इस संदर्भ में यह अवलोकन किया गया था कि "संशोधन" शब्द का उपयोग करते समय वहां विचाराधीन कानून का इरादा यह था कि केंद्र सरकार भाग ग राज्यों में बिना किसी आमूलचूल परिवर्तन के कुछ कानूनों का विस्तार करेगी। लेकिन वर्तमान मामले में हमें कला में उपयोग किए गए "संशोधन" शब्द के अर्थ का पता लगाना होगा। संविधान के संदर्भ में 370 (1) जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अनुच्छेद को लागू करने के पीछे का उद्देश्य है। 370 (1) जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को मान्यता देने और राष्ट्रपति को

ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ उस राज्य में संविधान के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति देकर उस विशेष स्थिति का प्रावधान करने के लिए था जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि अपवाद करने की शक्ति का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति यह प्रावधान कर सकते हैं कि संविधान का कोई विशेष प्रावधान उस राज्य पर लागू नहीं होगा। यदि इसलिए राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाले संविधान के किसी भी प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करने की शक्ति दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि जब उन्हें संशोधन करने की शक्ति भी दी जाती है तो उस शक्ति पर व्यापक संभव विस्तार में विचार किया जाना चाहिए। यदि वह जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होने वाले संविधान के किसी विशेष प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, तो हमें यह सोचने का कोई कारण नहीं दिखता है कि संविधान का इरादा यह नहीं था कि उसे जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होने वाले किसी विशेष प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जब संविधान ने कला में "संशोधन" शब्द का उपयोग किया था। 370 (1) उद्देश्य यह था कि राष्ट्रपति को संविधान के उपबंधों में संशोधन करने की शक्ति होगी, यदि वह जम्मू और कश्मीर राज्य में उनके अनुप्रयोग में ऐसा उचित समझता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में (खंड VI) 'संशोधित' शब्द का अर्थ है अन्य बातों के साथ-साथ "आंशिक परिवर्तन करना; इसके कुछ गुणों के संबंध में (वस्तु के रूप में) परिवर्तन करना; आमूल परिवर्तन के बिना परिवर्तन या परिवर्तन करना"। इसी तरह "संशोधन" शब्द का अर्थ है "किसी वस्तु की आवश्यक प्रकृति या चरित्र को बदले बिना उसमें परिवर्तन करने की क्रिया; इस प्रकार परिवर्तित होने की स्थिति; आंशिक परिवर्तन"। याचिकाकर्ता की ओर से "आमूलचूल परिवर्तन के बिना परिवर्तन या परिवर्तन" के अर्थ पर जोर दिया जा रहा है; लेकिन "संशोधित" या "संशोधन" शब्दों का यही एकमात्र अर्थ नहीं है। "संशोधित" शब्द का अर्थ "आंशिक परिवर्तन करना" और "संशोधन" का अर्थ "आंशिक परिवर्तन" भी है। यदि इसलिए राष्ट्रपति ने प्रत्यक्ष चुनाव के तरीके को अप्रत्यक्ष चुनाव में बदल दिया तो वह संक्षेप में अनुच्छेद में आंशिक परिवर्तन या आंशिक परिवर्तन कर रहे थे और इसलिए वर्तमान मामले में किया गया संशोधन उस शब्द के शब्दकोश अर्थ के भीतर भी होगा। लेकिन, कानून में, "संशोधित" शब्द का और भी व्यापक अर्थ है। रोलैंड बरोज के शब्दों और वाक्यांशों में, "संशोधित" शब्द का प्राथमिक अर्थ "सीमित करना" या "प्रतिबंधित करना" के रूप में दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ "भिन्न होना" भी है और इसका अर्थ "बढ़ाना" या "बड़ा करना" भी हो सकता है। इस प्रकार कानून में "संशोधित" शब्द का अर्थ केवल "भिन्न" हो सकता है, जो., संशोधन; और जब अनुच्छेद 370 (1) का कहना है कि राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के प्रावधानों को ऐसे संशोधनों के साथ लागू कर सकते हैं जो वह आदेश द्वारा

निर्दिष्ट कर सकते हैं इसका मतलब है कि वह जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके आवेदन में संविधान के प्रावधानों को बदल सकता है (जो, संशोधन)। इसलिए हमारी राय है कि संविधान के संदर्भ में हमें अनुच्छेद में प्रयुक्त 'संशोधन' शब्द के अर्थ को व्यापक प्रभाव देना चाहिए। 370 (1) और उस अर्थ में इसमें एक संशोधन शामिल है। अनुच्छेद में उपयोग किए गए "संशोधन" शब्द को सीमित करने का कोई कारण नहीं है। 370 (1) केवल ऐसे संशोधनों के लिए जो कोई "मौलिक परिवर्तन" नहीं करते हैं। [पृष्ठ 692-693]

15. यह तर्क दिया गया है कि संसदीय कानून को राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता होगी इससे पहले कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 370 लागू हो सके। यह अनुच्छेद 370 का पूरी तरह से गलत अध्ययन है जो यह स्पष्ट करता है। एक बार जब संघ सूची या समवर्ती सूची में से किसी एक मामले को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो आगे किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में, तर्क यह है कि एक संवैधानिक संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 368 के प्रावधान के तहत लागू नहीं होता है, जैसा कि उक्त राज्य में लागू होता है, जब तक कि राज्य सरकार की सहमति न हो और इसलिए, तार्किक रूप से, इसका पालन करना चाहिए कि संसदीय विधान को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होने से पहले राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता होगी। हम इस तरह के तर्क को समझने या उसकी सराहना करने में विफल रहते हैं। एक संवैधानिक संशोधन एक सामान्य कानून से गुणवत्ता में अलग है और जैसा कि हमारे द्वारा माना गया है, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 368 के प्रावधान की भाषा और अनुच्छेद 370 की भाषा अलग है और इसे उनकी शर्तों के अनुसार लागू किया जाना है।

16. जम्मू और कश्मीर राज्य के विलय का दस्तावेज दिनांक 26.10.1947 है, और अनुच्छेद 1,3,8 और 9 में निम्नलिखित कहा गया है:

"1. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत अधिराज्य को इस आशय से स्वीकार करता हूँ कि अधिराज्य के प्रयोजनों के लिए स्थापित भारत के गवर्नर जनरल, अधिराज्य विधानमंडल, संघीय न्यायालय और कोई अन्य अधिराज्य प्राधिकरण मेरे विलय के दस्तावेज के आधार पर, लेकिन हमेशा इसकी शर्तों के अधीन रहेगा, और केवल अधिराज्य के प्रयोजनों के लिए, जम्मू और कश्मीर राज्य (इसके बाद "इस राज्य" के रूप में संदर्भित) के संबंध में ऐसे कार्यों का प्रयोग करेगा जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा या उसके तहत निहित

हो सकते हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अधिराज्य लागू है, (जो अधिनियम इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है)

3. मैं यहां अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों को उन मामलों के रूप में स्वीकार करता हूँ जिनके संबंध में अधिराज्य विधानमंडल इस राज्य के लिए कानून बना सकता है।

8. इस लिखत में कुछ भी इस राज्य में और उस पर मेरी संप्रभुता की निरंतरता को प्रभावित नहीं करता है, या, इस लिखत द्वारा या उसके तहत प्रदान की गई किसी भी शक्ति, अधिकार और अधिकारों के प्रयोग के अलावा, जो अब इस राज्य के शासक के रूप में मुझे प्राप्त है या इस राज्य में वर्तमान में लागू किसी कानून की वैधता को प्रभावित करता है।

9. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं इस लिखत को इस राज्य की ओर से निष्पादित करता हूँ और इस लिखत में मेरे या राज्य के शासक के लिए किसी भी संदर्भ का अर्थ मेरे उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के संदर्भ के रूप में लगाया जाना है।

खंड 3 में निर्दिष्ट अनुसूची रक्षा, विदेशी मामलों, संचार और कुछ सहायक मामलों को संदर्भित करती है।

17. इस स्तर पर, यह देखना आवश्यक है कि भारत के संविधान के किन प्रावधानों को वास्तव में अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 370 के उपखंड (1) (ग) और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को इस उपखंड के आधार पर सीधे लागू होने के लिए कहा जाता है। यह पता लगाने के लिए कि संविधान के किन अन्य प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित किया गया है, हमें 1950 के राष्ट्रपति के आदेश पर जाना होगा। यह आदेश, जिसे संविधान अनुप्रयोग कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर आदेश, 1950, अनुसूची 7 की सूची। में कुछ प्रविष्टियों का विस्तार करके और संविधान के केवल कुछ खंडों और अनुच्छेदों को लागू करके शुरू हुआ। चूंकि यह आदेश और इसके संशोधन केवल ऐतिहासिक महत्व के हैं, इसलिए उन्हें किसी भी विस्तार से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह संविधान जम्मू और कश्मीर आदेश, 1954 पर लागू होता है, जिसने 1950 के आदेश को हटा दिया, और भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया, जिससे हम चिंतित हैं। जहां तक इस

मामले का संबंध है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाग 11 में, अनुच्छेद 246 में, यह कहा गया था कि खंड 1 में आने वाले "खंड 2 और 3 में कुछ भी निहित होने के बावजूद" शब्द, कोष्ठक और आंकड़े और खंड: 2, 3 और 4 को हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 254 को भी, अनुच्छेद 6 के उपखंड (च) द्वारा, कुछ संशोधनों और चूक के साथ बढ़ाया गया था। 7वीं अनुसूची संघ सूची को खंड 22 द्वारा स्पष्ट रूप से हटाए गए को छोड़कर उसमें अधिकांश प्रविष्टियों के साथ विस्तारित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रविष्टि 45 और 95, जिनसे हम सीधे तौर पर संबंधित हैं, इस आदेश द्वारा पहली बार आवेदन किए गए थे, और तब से राज्य में लागू होते रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से, राज्य सूची और 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची को मूल 1954 के आदेश द्वारा हटा दिया गया था।

18. इस आदेश को बाद के कई आदेशों द्वारा बार-बार संशोधित किया गया है, और जिस आदेश से हम सीधे संबंधित हैं, वह समय-समय पर संशोधित 1954 का आदेश है। यह आदेश कुछ संशोधनों और संशोधनों के साथ 20 जून, 1964 को लागू भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को अपनाता है। यह तर्क कि अनुच्छेद 370 (1) (ख) संसद की शक्ति को 'सीमित' करता है, इस तथ्य से उत्तर मिलता है कि भारत का संपूर्ण संविधान, जैसा कि 1964 में विद्यमान है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया है, इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 370 (1) (ख) और (घ) दोनों का लाभ उठाते हुए। और अभिव्यक्ति 'तक सीमित' अनुच्छेद 370 (1) (घ) में नहीं आती है जिसके तहत यह अपवादों और संशोधनों के अधीन भारत के पूरे संविधान को अपनाने के लिए खुला है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इस आदेश के प्रारंभिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

“ संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

1. (1) इस आदेश को संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 1954 कहा जा सकता है।

(2) यह मई, 1954 के चौदहवें दिन से प्रभावी होगा और उसके बाद संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू) आदेश, 1950 का स्थान लेगा।

2. 20 जून, 1964 को लागू संविधान के प्रावधान और संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966, संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967, संविधान की धारा 5 (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969, संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान की धारा 2 द्वारा

संशोधित। (पच्चीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान (तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1972, संविधान की धारा 2 (इकतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973, संविधान की धारा 2 (तैंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1974, संविधान की धारा 2, 5, 6 और 7 (अड़तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975, संविधान (उड़तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975, संविधान (चालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (5वाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2, 3 और 6 और संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 जो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त, संबंध में लागू होंगे जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए और वे अपवाद और संशोधन जिनके अधीन वे इस प्रकार लागू होंगे, इस प्रकार होंगे:-"

इस आदेश द्वारा भारत के संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 246 में खंड (1) में आने वाले "खंड (2) और (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "खंड (2)" शब्द, कोष्ठकों और आकृतियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और खंड (2) में आने वाले "खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी" शब्दों, कोष्ठकों और आकृतियों और पूरे खंड (3) और (4) को हटा दिया जाएगा। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाले अनुच्छेद 246 का पाठ इस प्रकार होगा: -

"246. संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु

(1) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची (इस संविधान में संघ सूची के रूप में निर्दिष्ट) की सूची I में प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है

(2) संसद और, खंड (1) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची (इस संविधान में समवर्ती सूची के रूप में निर्दिष्ट) की सूची III में प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है।

19. समान रूप से, अनुच्छेद 248 और प्रविष्टि 97 सूची 1 को संशोधित किया गया है ताकि संसद को केवल तीन विषयों के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति हो- (1) आतंकवादी कृत्यों से जुड़ी गतिविधियों की रोकथाम, (2) भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने या उसे बाधित करने या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से को सौंपने की दिशा में निर्देशित गतिविधियों की रोकथाम, और (3) तीन निर्दिष्ट विषयों पर कर। महत्वपूर्ण रूप से, परिपत्र आदेश संख्या 66 द्वारा खंड (च) जिसमें अनुच्छेद 254 को संशोधित रूप में शामिल किया गया था, को हटा दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया है

कि 1963 के पश्चात्, अनुच्छेद 254 अपने वर्तमान रूप में भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होगा। इसी तरह, 7वीं अनुसूची संघ सूची में, प्रविष्टियों की चूक अब केवल चार प्रविष्टियाँ 8,9,34 और 79 पर आ गई हैं, कुछ अन्य प्रविष्टियों को संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूची 1 की प्रविष्टियाँ 45 और 95 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होती हैं। राज्य सूची को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और 1963 के बाद से, समवर्ती सूची जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होती है जिसमें कई प्रविष्टियों को हटा दिया गया है। इस मामले के निर्णय के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित प्रविष्टि 6 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11क जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है, प्रविष्टि 6 लागू नहीं होती है क्योंकि इसे राज्य में विस्तारित नहीं किया गया है, और प्रविष्टि 11क लागू नहीं होती है क्योंकि भारत के संविधान में 42वां संशोधन, जिसने समवर्ती सूची में प्रविष्टि 11क को प्रस्तुत किया था, स्वयं लागू नहीं है।

20. इस स्तर पर, जम्मू और कश्मीर के संविधान, 1956 का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। यह संविधान 17.11.1956 को लागू हुआ। धारा 2 (1) (ए) और धारा 3,4, ए11डी 5 निम्नानुसार हैं:-

" 2. परिभाषाएँ:-

(1) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो- (क) "भारत का संविधान" से इस राज्य के संबंध में लागू भारत का संविधान अभिप्रेत है;

3. भारत संघ के साथ राज्य का संबंध: जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।

4. राज्य का राज्यक्षेत्र:-राज्य के राज्यक्षेत्र में वे सभी राज्यक्षेत्र सम्मिलित होंगे जो अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन राज्य के शासक की संप्रभुता या अधिराज्य के अधीन थे।

5. राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति का विस्तार:-राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति उन सभी मामलों को छोड़कर सभी मामलों में फैली हुई है, जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है।

21. इस संविधान में, जिसे वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू और कश्मीर राज्य

को भारत संघ का अभिन्न अंग बताया गया है और राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है, सिवाय उन मामलों के जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 370, समय-समय पर यथा संशोधित 1954 के राष्ट्रपति आदेश और जम्मू और कश्मीर के संविधान, 1956 के संयुक्त पठन से जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य की तुलना में भारत की संसद की विधायी क्षमता का संबंध है, निम्नलिखित स्थिति प्राप्त होगी:

1. भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 में निहित 1954 के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट सभी प्रविष्टियां उन प्रविष्टियों में निर्धारित विषय मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करेंगी।

2. समान रूप से , प्रविष्टि में निहित अवशिष्ट शक्ति के तहत 97 सूची में अनुच्छेद 248 के साथ पढ़ा, निर्दिष्ट विषय निर्धारित बाहर इंगित करेगा कि संसद की अवशिष्ट शक्ति उपरोक्त विषय मामलों से संबंधित विशेष कानूनों को लागू करने के लिए केवल उपरोक्त विषय मामलों के लिए और कोई आगे विस्तार होगा।

3. भारत की संसद को भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची III के तहत 1954 के राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट की गई प्रविष्टियों के संबंध में जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ समवर्ती शक्ति होगी। इसका अर्थ यह होगा कि अनुच्छेद 254 पर लागू सिद्धांत के प्रतिकूलता पर इस न्यायालय के सभी निर्णय उन कानूनों पर पूरी तरह से लागू होंगे जो इन विषय मामलों से संबंधित हैं।

4. परतेयक अन्य विषय जो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची I या सूची III, जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू के रूप में में संदर्भित नहीं है, जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है।

22. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में यथा मूल रूप से अपनाए गए विषयों पर रोक लगा दी गई थी और जब तक अनुच्छेद 370 बना रहता है तब तक उन्हें कभी भी संसद को प्रत्यायोजित या प्रदत्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 (1) (ख) के अधीन राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि संसद को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए केवल संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विधान के क्षेत्रों पर कानून बनाने की शक्ति है।

हमें डर है कि यह निवेदन बिना किसी बल के भी है क्योंकि अनुच्छेद 368 का प्रावधान , जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में किसी भी संवैधानिक संशोधन को जम्मू और कश्मीर राज्य की सहमति से लागू करने की अनुमति देता है। इसमें एक संशोधन शामिल होगा जो या तो राज्य सूची में जोड़ता है या घटाता है और संसद को विशेष रूप से सूची 1 के तहत या समवर्ती रूप से सूची 111 के तहत प्रदान करता है, जो अब तक राज्य सूची में एक विषय है। **संपत प्रकाश के मामले** में ऐसा माना गया है (ऊपर) इसके अलावा, **पुरनलाल लखन पाल के मामले** (उपर्युक्त) में अनुच्छेद 370 (1)(घ) में होने वाले "संशोधन" अभिव्यक्ति का अर्थ न केवल "सीमित करना या प्रतिबंधित करना" बल्कि "विस्तार करना या बढ़ाना" भी है। इस प्रकार, "संशोधन" शब्द को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और इसमें वे सभी संशोधन शामिल होंगे जो या तो भारत के संविधान के प्रावधानों को सीमित करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं या विस्तारित करते हैं या विस्तारित करते हैं। यही कारण है कि यह भी स्पष्ट है कि जब तक अनुच्छेद 370 की कवायद का पालन किया जाता है, तब तक कुछ भी नहीं रोका जा सकता है।

23. इस विधायी परिदृश्य को देखते हुए, हमें अब जम्मू और कश्मीर राज्य में इसकी प्रयोज्यता में सरफेसी की जांच करनी होगी। सूची 1 की प्रविष्टियाँ 45 और 95 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का इस प्रकार हैं:-

"45. बैंकिंग।

95. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां; नौसेना अधिकारिता।

24. ध्यान देने वाली पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली प्रविष्टि 45 सूची 1 के अंतर्गत आती है। इस प्रकार, **भारत संघ बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन**, (2002) 4 एस. सी. सी. 275 में यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"दिल्ली उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना से संबंधित विधि अधिनियमित करने की संसद की शक्ति का स्रोत सूची 111 की प्रविष्टि 11-क है जो" न्याय के प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों के गठन और संगठन "से संबंधित है। हमारी राय में, सूची 1 की प्रविष्टि 45 में अब अधिनियमित विधानों के प्रकार शामिल होंगे। सूची 1 की प्रविष्टि 45 "बैंकिंग" से संबंधित है। बैंकिंग परिचालन में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणों और जमा

स्वीकार करना, ऋण देना और बैंक को देय ऋणों की वसूली शामिल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सूची 1 की प्रविष्टि 45 के तहत, यह केवल संसद ही है जो बैंकों द्वारा व्यवसाय के संचालन के संबंध में कानून बना सकती है। बकाया की वसूली किसी भी बैंकिंग संस्थान का एक आवश्यक कार्य है। बैंकिंग से संबंधित अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद वह तंत्र प्रदान कर सकती है जिसके द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय धन की वसूली की जा सकती है। इस संबंध में न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है। बैंकों के ऋण के लिए। न्यायाधिकरण का विशेष तंत्र, जिसका गठन अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार किया गया है, "बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली के लिए और उनसे जुड़े या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए" पूरी तरह से सूची 1 की प्रविष्टि 45 के दायरे में आएगा। चूंकि सूचियों में से किसी भी वस्तु को संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थ में नहीं पढ़ा जाना है, इसलिए प्रविष्टि 45 में "बैंकिंग" शब्द का अर्थ बैंकिंग से संबंधित सहायक या सहायक मामलों सहित बैंकिंग के सभी पहलुओं के बारे में कानून बनाना होगा। लेन-देन, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान संबंधित हैं, से संबंधित बैंकिंग ट्रिब्यूनल जैसे न्यायिक निकाय की स्थापना स्पष्ट रूप से सूची 1 की प्रविष्टि 45 के अंतर्गत आती है, जो संसद को उसके संबंध में कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति देती है। "[अनुच्छेद 14]

25. सरफेसी की बात आती है तो इस न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य (2009) 4 एस.सी.सी. 94 में यह निर्णय दिया है:

"निर्विवाद रूप से, ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम और प्रतिभूतिकरण अधिनियम को संसद द्वारा 7वीं अनुसूची में सूची 1 में प्रविष्टि 45 के तहत अधिनियमित किया गया है, जबकि बॉम्बे और केरल अधिनियमों को 7वीं अनुसूची में सूची 11 में प्रविष्टि 54 के तहत संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित किया गया है। अलग-अलग शब्दों में कहें तो 7वीं अनुसूची की विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के संदर्भ में दो प्रकार के विधान बनाए गए हैं। इसलिए, राज्य विधानों को इस आधार पर निरस्त करने के लिए अनुच्छेद 254 का उपयोग नहीं किया जा सकता है कि वे केंद्रीय विधानों के साथ संघर्ष में हैं। इसके अलावा, जैसा कि आगे देखा जाएगा, विधानों के दो समूहों के बीच कोई स्पष्ट रूप से अतिव्यापी नहीं है। इसलिए, भले ही केसोरम इंडस्ट्रीज मामले [(2004) 10SCC 201] में निहित टिप्पणियों को संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून के रूप में माना जाता है, राज्य विधानों को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि वे केंद्रीय विधानों के साथ संघर्ष में हैं। [अनुच्छेद 36]

26. हाल के एक फैसले में, यूको बैंक और ए.एन.आर.वी. दीपक देबबर्मा और अन्य, [सिविल अपील संख्या का 11247 /2016 और सिविल अपील संख्या 11250/2016] इस न्यायालय द्वारा 25 नवंबर, 2016 को दिया गया, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

18. . 2002 का अधिनियम बैंकिंग की प्रविष्टि से संबंधित है जो 7वीं अनुसूची की सूची । में शामिल है। बैंक द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है। राज्य अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, राज्य में भूमि राजस्व कानून को मजबूत करने और जी कृषि सुधारों के उपाय प्रदान करने का एक प्रयास है। राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए अतिक्रमण का क्षेत्र बैंकिंग के क्षेत्र में है। जब तक सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित और सूची । की प्रविष्टि 45 के लिए संदर्भित कोई समानांतर केंद्रीय अधिनियम मौजूद नहीं था, तब तक धारा 187 सहित राज्य अधिनियम वैध रूप से संचालित था। तथापि, जिस क्षण संसद ने प्रविष्टि 45 से पता लगाने योग्य ऐसी विधि अधिनियमित करके और विशेष रूप से सुरक्षित आस्तियों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए कदम उठाया, राज्य विधि को इस हद तक कि वह 2002 के अधिनियम के साथ असंगत है, छूट देनी चाहिए। प्रमुख विधान संसदीय विधान है, 1960 के त्रिपुरा अधिनियम के प्रावधान, प्रो टैन्टो, (धारा 187) अमान्य होगा। यह 2002 के अधिनियम के प्रावधान हैं, जिसमें उन व्यक्तियों की श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिन्हें बैंक द्वारा अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति बेची जा सकती है, जो त्रिपुरा अधिनियम 1960 की धारा 187 में निहित प्रावधानों पर प्रबल होगा।

27. इस मामले में, त्रिपुरा भूमि सुधार कानून, जिसे सूची II की प्रविष्टि 18 और 45 के तहत बनाया गया था, को सरफेसी के खिलाफ खड़ा किया गया था, जिसे प्रविष्टि 45 सूची I के तहत बनाया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि त्रिपुरा अधिनियम को नौवीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31ख का संरक्षण प्राप्त हुआ था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि त्रिपुरा अधिनियम, जिसकी धारा 187 किसी भी व्यक्ति को, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, बैंक द्वारा गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री पर विधायी प्रतिबंध लगाती है, प्रविष्टि 45 सूची I के तहत बनाए गए संसदीय अधिनियम सरफेसी को रास्ता देने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था। यद्यपि यह निर्णय वर्तमान मामले के सभी चार पक्षों पर लागू नहीं होता है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि सरफेसी प्रविष्टि 45 सूची I से संबंधित है और राज्य सूची के तहत किए गए किसी भी अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आवेदन के आधार पर सरफेसी को रास्ता देना होगा।

28. आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ, (1970) 1 एस.सी.सी. 248 ने भी अनुच्छेद 36 में कहा है कि प्रविष्टि 45 सूची । में विषय वस्तु 'बैंकिंग' का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि इसके दायरे में उन सभी मामलों को समझा जा सके जो ऐसे विषय के लिए आकस्मिक हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"7वीं अनुसूची की सूची । में विधायी प्रविष्टि" बैंकिंग "है न कि" बैंकर "या" बैंक "। प्रविष्टि 45, सूची । में "बैंकिंग" शब्द के अर्थ के भीतर शामिल करने के लिए, सभी वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, जिसमें बैंकों की प्रथा या कानून के अधिकार से एक बैंकर संलग्न होता है, के परिणामस्वरूप संविधान का पुनर्लेखन होगा। एक निर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति के निवेश में विषय से जुड़े सभी प्रासंगिक मामले शामिल हैं। पूर्ण शक्ति की आकृति को इंगित करने वाले एक व्यापक पदनाम में व्यक्त की जा रही एक विधायी प्रविष्टि को व्यापक आयाम के लिए अनुकूल अर्थ प्राप्त होना चाहिए, हालांकि संघीय योजना में निहित सीमाओं के अधीन जो संघ और घटक इकाइयों के बीच विधायी शक्ति का वितरण करती है। "बैंकिंग" के क्षेत्र को उन व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जो सूची ॥ में "व्यापार और वाणिज्य" की प्रविष्टि के सार पर बैंकिंग अतिक्रमण के लिए आकस्मिक नहीं हैं। [अनुच्छेद 36]

29. कनाडा के महान्यायवादी बनाम क्यूबेक प्रांत के महान्यायवादी, 1947 अपील मामले 33 में रिपोर्ट किया गया प्रिवी काउंसिल का एक निर्णय भी इस बात पर कुछ प्रकाश डालता है कि "बैंकिंग" अभिव्यक्ति का सही अर्थ क्या है। एक क्यूबेक कानून जिसे खाली संपत्ति के रूप में माना जाता है, एक मालिक के बिना, (जो अब महामहिम से संबंधित होगा) क्रेडिट संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में सभी जमा या क्रेडिट जो जमा पर धन या प्रतिभूतियां प्राप्त करते हैं, जहां 30 साल या उससे अधिक समय के लिए ऐसी जमा या क्रेडिट इसके हकदार व्यक्तियों द्वारा किसी भी संचालन या दावे का विषय नहीं हैं। क्यूबेक प्रांत की कोर्ट ऑफ किंग्स बैंच की एक अपील में, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल ने तर्क दिया कि राज्य अधिनियम क्यूबेक विधायिका की शक्तियों से परे था क्योंकि "बैंकिंग" विशेष रूप से कनाडा की संसद को आवंटित विषयों में से एक था। लॉर्ड पोर्टर ने एक सुनहरे फैसले में सवाल उठाया और इसका जवाब इस प्रकार दिया: -

"तो क्या कानून के तहत जमाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों को जमाओं का पुनर्भुगतान बैंकिंग व्यवसाय का एक हिस्सा है या अनिवार्य रूप से प्रासंगिक है, या यह मुख्य रूप से संपत्ति और नागरिक अधिकारों से संबंधित है या उन विषयों के लिए प्रासंगिक है? उनके स्वामी यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि जमाओं की प्राप्ति और जमाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों को जमा की गई राशि का पुनर्भुगतान, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बैंकिंग व्यवसाय का एक अनिवार्य हिस्सा है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रिवी काउंसिल ने आगे कहा:

"उनके विचार में, एक प्रांतीय विधायिका बैंकिंग के क्षेत्र में तब प्रवेश करती है जब वह जमाकर्ताओं के जमा का भुगतान प्राप्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप करती है, जैसा कि उनके विचार में यह होगा यदि वह किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण को जब्त कर लेती है। दोनों एक अर्थ में संपत्ति और नागरिक अधिकारों के मामले हैं, लेकिन संक्षेप में वे बैंकिंग की श्रेणी में शामिल हैं। (पृष्ठ 44 और 46 पर)

30. ध्यान देने योग्य बात यह है कि चूंकि सूची-11 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, इसलिए उक्त सूची में कोई प्रतिस्पर्धी प्रविष्टि नहीं है और इसलिए यह निष्कर्ष निकालता है कि सूची-11 की प्रविष्टि 45 और 95 को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। वास्तव में, एक विपरीत स्थिति में, यह न्यायालय, **भारत संघ बनाम एच.एस.दिल्लों**, 1972 (2) एस.सी. आर.33 में यह कहा गया था:

"यह भी कहा गया था कि यदि संविधान निर्माताओं की यही मंशा थी तो उन्हें सूची 1 तैयार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। यह वह बिंदु है जिसे सरदार हुकुम सिंह और अन्य लोगों ने ऊपर उल्लिखित बहसों में लिया था और इसका उत्तर डॉ. अम्बेडकर ने दिया था। लेकिन डॉ. अम्बेडकर द्वारा ऊपर निकाले गए अपने भाषण में जो कहा गया है, उसके अलावा सूची 1 में विशिष्ट वस्तुओं को शामिल करने में कुछ योग्यता और कानूनी प्रभाव है क्योंकि जब तीन सूचियां होती हैं तो सूची 1 और 11 के आलोक में सूची 11 का अर्थ लगाना आसान होता है। यदि कोई सूची 1 नहीं होती, तो सूची 11 में कई मदों को शायद वर्तमान योजना के तहत दी जा सकने वाली व्याख्या से कहीं अधिक व्यापक व्याख्या दी जाती। जो भी हो, हमारे पास तीन सूचियां और एक अवशिष्ट शक्ति है और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में यदि किसी केंद्रीय अधिनियम को संसद की विधायी क्षमता से परे होने के रूप

में चुनौती दी जाती है, तो यह जांच करने के लिए पर्याप्त है कि क्या यह सूची ॥ में सूचीबद्ध मामलों या करों के संबंध में एक कानून है। यदि ऐसा नहीं है, तो आगे कोई सवाल नहीं उठता। (पृष्ठ 67 पर)

31. इस मोड़ पर, यह पता करने के लिए महत्वपूर्ण है **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम एम। एस. फारूकी**, (1972)। एस.सी.सी. 872. यह निर्णय अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1955 के विरुद्ध जम्मू और कश्मीर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण (आयोग) अधिनियम, 1962 के बीच अंतःक्रिया से संबंधित था। निर्णय के अनुच्छेद 7 में यह देखा गया कि संसद अखिल भारतीय सेवाओं पर प्रविष्टि 70 सूची। के आधार पर विधान बना सकती है और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम इस प्रविष्टि के लिए संदर्भित हैं। इस न्यायालय को इस प्रश्न का उत्तर देना था कि क्या अपीलार्थी, जो जम्मू और कश्मीर संवर्ग में भारतीय पुलिस सेवा, जो कि एक अखिल भारतीय सेवा है, का सदस्य था, अखिल भारतीय सेवा नियमों या जम्मू और कश्मीर अधिनियम द्वारा शासित होने के लिए उत्तरदायी था। विधायी क्षमता पर इस न्यायालय के निर्णयों के साथ कुछ विस्तार से विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:-

उन्होंने कहा, "दो वैधानिक कानूनों, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1955 और जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण (आयोग) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अवलोकन से इस निष्कर्ष से बचना असंभव है कि दोनों एक साथ नहीं जा सकते। विवादित अधिनियम अतिरिक्त दंड का प्रावधान करता है जो अनुशासन और अपील नियमों में प्रदान नहीं किया गया है। इसमें निलंबन और कुछ दंड देने का भी प्रावधान है। हमें ऐसा लगता है कि जहां तक आयोग अधिनियम अनुशासनात्मक दंड देने से संबंधित है, यह अनुशासन और अपील नियमों के प्रतिकूल है। संसद ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और स्पष्ट संकेत दिया है कि यह ऐसा केंद्र था जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक आयोग अधिनियम किसी भी अभियोजन को शुरू करने में सक्षम बनाने के उद्देश्यों के लिए प्रारंभिक जांच से संबंधित है, यह जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी क्षमता के भीतर हो सकता है और अनुशासन और अपील नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि संभावित आपराधिक अभियोजन के लिए जांच से संबंधित प्रावधान अनुशासनात्मक दंड देने से संबंधित प्रावधानों के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे अधिनियम को पढ़ा जाना चाहिए ताकि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखा जा सके।

तदनुसार हमारा मानना है कि आयोग अधिनियम के प्रावधान सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवाएँ।

इसलिए हम याचिका को खारिज करते हैं। चूंकि प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, इसलिए लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। हम श्री जी. एल. संघी को धन्यवाद देते हैं। न्यायमित्र के रूप में हमारी सहायता करने के लिए "। [अनुच्छेद 47-48]

32. सारफेसी में सार और तथ्य के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि सार और तथ्य में पूरा अधिनियम प्रविष्टि 45 सूची के लिए संदर्भित है, प्रविष्टि 95 सूची के साथ पढ़ा जाता है कि यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की सुविधा के माध्यम से, और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। सारफेसी "संपत्ति के हस्तांतरण" से संबंधित नहीं है। वास्तव में, जहां तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का संबंध है, यह ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली से संबंधित है और इस तरह की वसूली को लागू करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया के बाहर कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सरफेसी की धारा 13 (4) के तहत, उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने और उनके ऋणों की वसूली के लिए उन्हें सौंपने या बेचने के अलावा, बैंक उधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन भी कर सकते हैं; और/या सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित लेनदार के रूप में बैंक किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा किसी भी व्यक्ति से, जिसने उधारकर्ता से किसी भी सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण किया है और जिससे पैसा उधारकर्ता को देय या देय है, सुरक्षित लेनदार को इतना पैसा देने की आवश्यकता कर सकते हैं जितना कि सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिक्री या समनुदेशन के रूप में संपत्ति का अंतरण, बैंक को देय सुरक्षित ऋण की वसूली के कई उपायों में से केवल एक है और यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि सरफेसी, समग्र रूप से, संभवतः सार और तथ्य में नहीं कहा जा सकता है, एक अधिनियम जो "संपत्ति के हस्तांतरण" के मामले से संबंधित है। इस समय यह इंगित करना आवश्यक है कि जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य का संबंध है, सरफेसी की धारा 17 क और धारा 188, जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होती है, को क्रमशः 'जिला न्यायाधीश' और 'उच्च न्यायालय' के स्थान पर 'ऋण वसूली

अधिकरण' और 'अपीलीय अधिकरण' के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"धारा 17-क कुछ मामलों में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करना। जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले उधारकर्ता के मामले में, धारा 17 के तहत आवेदन उस राज्य के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में किया जाएगा, जो उधारकर्ता पर अधिकार क्षेत्र रखता है, जो ऐसे आवेदन पर आदेश पारित करेगा।

व्याख्या- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कारणों के संचार के स्तर पर अपने प्रतिनिधित्व या आपत्ति या सुरक्षित लेनदार की संभावित कार्रवाई को स्वीकार नहीं करने के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा उधारकर्ता को कारणों के बारे में संचार इस धारा के तहत जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करने के लिए व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) को हकदार नहीं करेगा।

धारा 18ख कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में अपील

जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाला और धारा 17क के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी उधारकर्ता जिला न्यायाधीश के न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे न्यायालय पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि कोई भी अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उधारकर्ता ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में, उससे देय ऋण की राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया है, जैसा कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा दावा किया गया है या जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जो भी कम हो:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, राशि को पहले प्रावधान में निर्दिष्ट ऋण के पच्चीस प्रतिशत से कम न कर सके।

33. यह स्पष्ट होगा कि ये उपबंध प्रविष्टि 45 के लिए बैंकिंग के सहायक होने के रूप में और प्रविष्टि 95 सूची 1 के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भित हैं-क्योंकि न्यायालयों की अधिकारिता और शक्ति इन उपबंधों द्वारा बैंकों को देय ऋणों की वसूली के विशेष विषय के लिए निर्धारित की गई है।

34. **महाराष्ट्र राज्य बनाम नरोत्तमदास जेठाबई**, (1950) 1 एससीआर 51 में, इस न्यायालय ने बाम्बे सिटी सिविल कोर्ट अधिनियम को बरकरार रखा और इस प्रकार करते हुए, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की विधायी सूचियों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया।

प्रविष्टि 53, सूची I:

"इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ"...

"प्रविष्टि 1 और 2, सूची 2:

"1... न्याय का प्रशासन; संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन"...

2. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ.."

प्रविष्टि 15, सूची III

" इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की न्यायपालिका और शक्तियाँ।"

35. न्यायमूर्ति फजल अली, महाजन और मुखर्जी ने अभिनिर्धारित किया कि भारत सरकार अधिनियम, 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 1 में 'निहित' न्याय प्रशासन 'में आम तौर पर न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ शामिल होंगी, लेकिन सूची 1 की प्रविष्टि 53 प्रविष्टि 1 सूची 2 में निहित सामान्य शक्ति के विपरीत संघ सूची में किसी विशेष प्रविष्टि के लिए निर्दिष्ट विशेष शक्तियों को संदर्भित करेगी। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रविष्टि 53 सूची 1 जैसे स्पष्ट उपबंध के लिए संसद विधायी सूची 1 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में न्यायालयों को विशेष अधिकारिता प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती है। दो विद्वान न्यायाधीश, पतंजलि शास्त्री और दास, बाम्बे अधिनियम को भी बरकरार रखा, लेकिन इस आधार पर कि "न्याय प्रशासन" अभिव्यक्ति को "सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्ति" अभिव्यक्ति द्वारा काट दिया जाएगा, और इसलिए इसके अधिकार क्षेत्र और न्यायालयों की शक्ति के भीतर शामिल नहीं होगा।

36. इसी प्रकार **जमशेद एन. गुजदार बनाम महाराष्ट्र राज्य** (2005) 2 एस.सी.सी. 591 में, इस न्यायालय ने बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट और बॉम्बे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस (विशिष्ट अधिकारिता में वृद्धि और संशोधन) अधिनियम, 1986 की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 53 में इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हुए बरकरार रखा:

"इस प्रकार, 3-1-1977 को और उसके बाद की स्थिति इस प्रकार प्रतीत होती है:

(क) अकेले संसद को उच्च न्यायालय का गठन और आयोजन करने के लिए सूची 1 की प्रविष्टि 78 के संबंध में विधान बनाने की क्षमता है।

(ख) संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही सूची III की प्रविष्टि 11क के अधीन "न्याय प्रशासन" के लिए निर्दिष्ट एक उपयुक्त विधान अधिनियमित करके सामान्य अधिकारिता वाले ऐसे उच्च न्यायालय का निवेश कर सकते हैं।

(ग) संसद, सूची 1 की प्रथम प्रविष्टि 95 के अधीन, सूची 1 में वर्णित किसी भी मामले के संबंध में उच्च न्यायालय को अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है।

(घ) राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय को सूची 2 में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकता है।

(ङ) संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही सूची-III की प्रविष्टि 46 को संदर्भित उचित विधान द्वारा सूची-III में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उच्च न्यायालय को अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। [अनुच्छेद 53]

37. इस प्रकार इन निर्णयों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि सरफेसी समग्र रूप से सूची 1 की प्रविष्टियों 45 और 95 के लिए संदर्भित होगा। हमें **ए.एस. कृष्णा और अन्य बनाम मद्रास राज्य**, 1957 एससीआर 399 में इस न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी को याद रखना चाहिए कि पहले किसी अधिनियम को विभिन्न भागों में विभाजित करना और फिर उन भागों को विधायी सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए संदर्भित करना सही नहीं है। अतः धारा 17क और 18ख सहित संपूर्ण अधिनियम, सूची 1 की प्रविष्टियां 45 और 95 के लिए निर्दिष्ट होगा और इसलिए समग्र रूप से अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में अनिवार्य रूप से कार्य करेगा।

38. समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11क का उल्लेख करने में उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह प्रविष्टि जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित नहीं है। इससे, प्रत्यर्थियों के वकील ने यह तर्क देना चाहा कि इसलिए, संसद के पास समवर्ती सूची के तहत "न्याय प्रशासन" विषय पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 के तहत, हमने देखा है कि "न्याय प्रशासन" तभी लागू होगा जब सूची 1 की प्रविष्टियां 45 और 95 आकर्षित नहीं की जाएंगी। भले ही ऐसा न हो, हमने ऊपर दिए गए दो निर्णयों में देखा है कि "न्याय का प्रशासन" अभिव्यक्ति सामान्य है और इसे उन विशेष कानूनों को रास्ता देना चाहिए जो प्रविष्टि 95 सूची 1 के तहत अधिनियमित हैं जब उसी सूची में एक और प्रविष्टि के साथ जोड़ा जाता है- इस मामले में प्रविष्टि 45 सूची 1। जम्मू और कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 140 का प्रासंगिक भाग, जिस पर प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है, प्रदान करता है:-

"140 अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों से कुछ उपकरणों को छूटा। इरशाद दिनांक 29 मगहर, 1943 में या किसी विधि, नियम आदेश, अधिसूचना, कानून, आदेश, परिपत्र, रोबकर, यादस्त, इरशाद, राज्य परिषद संकल्प या किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, जो राज्य स्थायी निवासी नहीं है, अचल संपत्ति के अंतरण को प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने वाले विधि के बल वाले किसी अन्य लिखत में निहित कुछ भी नहीं है, इस पर लागू होगा-

(ज) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के पक्ष में निष्पादित या सृजित अचल संपत्ति का साधारण बंधक,। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में उस समय के लिए एक अनुसूचित बैंक और डिबेंचर धारकों के लिए न्यासी जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की जम्मू और कश्मीर राज्य विकास परियोजना की तरह जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की अन्य वित्तीय परियोजनाओं के लिए ऋण, ऋण की गारंटी, गारंटी या अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बशर्ते कि ऐसे बंधक पर आधारित किसी वाद में, गिरवी रखी गई संपत्ति को केवल राज्य के स्थायी निवासी या भारत सरकार द्वारा प्रबंधित और स्वामित्व वाले किसी वित्तीय संस्थान या निगम को बेचा या हस्तांतरित किया जाएगा;

39. इस समय, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है: -

“बशर्ते कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अचल संपत्ति की बिक्री के मामले में, जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1977 के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होंगे जो राज्य में ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है।”

40. यह नियम यह स्पष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर के संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 का राज्य के भीतर होने वाली नीलामी बिक्री में सम्मान किया जाएगा। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि सरफेसी के किसी भी प्रावधान के साथ कोई टकराव या प्रतिकूलता नहीं है, और इसलिए यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में बिल्कुल गलत है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 का उल्लंघन किया जाएगा, सरफेसी को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। नियम 8 पर ध्यान दिया गया है लेकिन उपरोक्त निर्णय द्वारा इसे दरकिनार कर दिया गया है। उच्च न्यायालय का निर्णय गलत अंत से शुरू होता है और इसलिए गलत निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 5 के संदर्भ में, राज्य के पास अपने स्थायी निवासियों के अचल संपत्तियों के अधिकारों को छूने वाले कानूनों के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण संप्रभु शक्ति है। राज्य विधायिका ने जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 को अधिनियमित किया है, इसलिए, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के विषय/नागरिक उक्त प्रावधान के आधार पर संरक्षित हैं, सरफेसी इस तरह के संरक्षण में घुसपैठ और बाधा नहीं डाल सकता है। पूरा तरीका गलत है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूची 1 की प्रविष्टियां 45 और 95 संसद को बैंकिंग के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करती हैं, और संपूर्ण सरफेसी को भारत के संविधान की सूची 1, 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 45 और 95 के लिए संदर्भित कहा जा सकता है। इस मामले में, जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 केवल उन क्षेत्रों में काम करेगी जहां संसद को राज्य के लिए कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर कानून के माध्यम से सरफेसी के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अनिवार्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर उक्त कानून को रास्ता देना चाहिए, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 5 के साथ पढ़ा जाता है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 13 (1) और (4) को

संसद की विधायी क्षमता से परे नहीं ठहराया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है।

41. यह देखना परेशान करने वाला है कि फैसले के विभिन्न हिस्से जम्मू और कश्मीर राज्य की पूर्ण संप्रभु शक्ति की बात करते हैं। यह दोहराना आवश्यक है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 3, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, एक महत्वपूर्ण घोषणा करती है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। और यह प्रावधान संशोधन के दायरे से बाहर है। जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 147 में कहा गया है:-

"147 संविधान में संशोधन। इस संविधान का संशोधन केवल इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। विधान सभा में और जब विधेयक प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, तो इसे सदर-ए-रियासत को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति दिए जाने पर संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित होगा:

परन्तु विधान परिषद के उन्मूलन का उपबंध करने वाला विधेयक विधान सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है और उसके द्वारा विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले विधानसभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि

(क) इस धारा में;

(ख) धारा 3 और 5 के उपबंधों में; या

(ग) भारत के संविधान के उपबंधों में, जो राज्य के संबंध में लागू हों,

विधानमंडल के किसी भी सदन में स्थापित या स्थापित किया जाएगा।

42. इस संदर्भ में जम्मू और कश्मीर के संविधान, 1957 की प्रस्तावना का उल्लेख करना और इसकी तुलना भारत के संविधान, 1950 से करना भी महत्वपूर्ण है।

जम्मू और कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है:

"हम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग, गंभीरता से संकल्प लेते हुए। भारत में इस राज्य का प्रवेश, जो अक्टूबर, 1947 के 26वें दिन हुआ था, भारत संघ के साथ राज्य के मौजूदा संबंधों को उसके अभिन्न अंग के रूप में और परिभाषित करने के लिए, और स्वयं को सुरक्षित करने के लिए-

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा;

स्थिति और अवसर की समानता; और हम सभी के बीच बढ़ावा देना;

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देना; हमारे संविधान में नवंबर, 1956 के इस सत्रहवें दिन, इस विषय को स्वीकार करें, स्थापित करें और स्वयं को दें।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के संविधान के प्रारंभिक अनुच्छेद, अर्थात् "हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए... " को जम्मू और कश्मीर के संविधान में पूरी तरह से हटा दिया गया है। संप्रभुता का कोई संदर्भ नहीं है न ही अपने लोगों का उल्लेख करते समय "नागरिक" अभिव्यक्ति का कोई उपयोग है। जम्मू और कश्मीर के लोग जिनके लिए संविधान में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग III के तहत "स्थायी निवासी" के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन सबसे ऊपर, जम्मू और कश्मीर का संविधान भारतीय संघ के साथ राज्य के मौजूदा संबंधों को उसके अभिन्न अंग के रूप में परिभाषित करने के लिए बनाया गया है।

43. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के पास भारत के संविधान और अपने स्वयं के संविधान के बाहर संप्रभुता का कोई निशान नहीं है, जो भारत के संविधान के अधीन है। इसलिए इसे संप्रभु होने के रूप में इस अर्थ में वर्णित करना पूरी तरह से गलत है कि इसके निवासी अपने आप में एक अलग और विशिष्ट वर्ग का गठन करते हैं। हमें उच्च न्यायालय को याद दिलाना होगा कि जम्मू-कश्मीर के निवासी सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। वास्तव में, यह जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 6 द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसमें कहा गया है:

“6. स्थायी निवासी:- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह राज्य का स्थायी निवासी होगा, यदि मई, 1954 के चौदहवें दिन-

(क) वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का राज्य विषय था; या

(ख) राज्य में विधिपूर्वक अर्जित अचल संपत्ति रखने वाला, वह उस तारीख से कम से कम दस वर्ष पहले से राज्य में साधारण निवासी रहा है।

(2) कोई भी व्यक्ति जो, मई, 1954 के चौदहवें दिन से पहले, राज्य विषय की श्रेणी I या श्रेणी II में वर्गीकृत था और जो मई, 1954 के पहले दिन के बाद प्रवास कर गया था। मार्च, 1947, अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में, राज्य में पुनर्वास के लिए परमिट के तहत राज्य को लौटता है या राज्य द्वारा या उसके तहत जारी किए गए वापसी के लिए। राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का प्राधिकारी ऐसी वापसी पर राज्य का स्थायी निवासी होगा।

(3) इस धारा में, "वर्ग I या वर्ग II का विषय" पद का वही अर्थ होगा जो राज्य अधिसूचना संख्या I-L/84 दिनांक 20 अप्रैल, 1927, राज्य अधिसूचना संख्या 13/एल दिनांक 27 जून, 1932 I।"

वे पहले भारत के संविधान और जम्मू और कश्मीर के संविधान द्वारा शासित होते हैं। यह जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 10 द्वारा स्पष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है:

“10. स्थायी निवासियों के अधिकार:- राज्य के स्थायी, निवासियों को भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत सभी अधिकार होंगे।

हमें इसका पालन करने के लिए विवश किया गया है क्योंकि कम से कम तीन स्थानों पर उच्च न्यायालय एक संप्रभुता का उल्लेख करने के लिए अपने रास्ते से हट गया है जो मौजूद नहीं है।

44. फिर से सूची 3 की प्रविष्टि 1क का उल्लेख करना और यह कहना पूरी तरह से गलत है कि चूंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तारित नहीं है, इसलिए संसद को सरफेसी की धारा 17क और 18ख को अधिनियमित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं होगी। इस निष्कर्ष में कम से कम तीन त्रुटियाँ हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफेसी की

मान्यताओं को अलग करना और उन्हें विभिन्न सूचियों के तहत विभिन्न प्रविष्टियों से जोड़ना संभव नहीं है। जैसा कि हमारे द्वारा माना गया है, संपूर्ण सरफेसी सूची 1 की प्रविष्टि 45 और 95 के लिए संदर्भित है। दूसरा, आक्षेपित निर्णय से जो छूट गया है वह यह है कि प्रविष्टि 95 सूची 1, सरफेसी में निहित मामलों के संबंध में क्रमशः जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय को शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए संसद के लिए विधायी शक्ति का एक स्रोत है। और तीसरा, विषय "न्याय प्रशासन" केवल सामान्य है और इसे केवल तभी संदर्भित किया जा सकता है जब प्रविष्टि 95 सूची में प्रविष्टि 45 सूची के साथ पढ़ा जाता है, आकर्षित नहीं होता है। हमें डर है कि **नरोत्तमदास जेठाबाई** और **जमशेद गुज़दार के मामले** (ऊपर) में फैसले के बावजूद उच्च न्यायालय भले ही यह **नरोत्तमदास जेठाबाई** को संदर्भित करता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही यह पाया गया हो कि जम्मू और कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 140 जम्मू और कश्मीर राज्य में केवल कुछ व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करती है, फिर भी, जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, नियम 8 (5) प्रावधान जो इस प्रावधान को मान्यता देता है, को दरकिनार कर दिया गया है। किसी भी मामले में पहले जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 को सरफेस के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा सामंजस्य असंभव है, तो यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के आधार पर, जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 को सरफेसी को रास्ता देना होगा, न कि इसके विपरीत।

45. रिलायंस को संविधान के अनुच्छेद 35क पर भी रखा गया है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है:

'35क। स्थायी निवासियों और उत्तराधिकारियों के अधिकारों के संबंध में कानूनों का संरक्षण- इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवृत्त कोई विद्यमान विधि नहीं है और इसके पश्चात् राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई विधि नहीं है-

(क) उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करना जो जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे; या

(ख) ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करना या अन्य व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाना-

(i) राज्य सरकार के अधीन रोजगार;

(ii) राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण;

(iii) राज्य में निपटान; या

(iv) छात्रवृत्ति और ऐसे अन्य प्रकार की सहायता का अधिकार जो राज्य सरकार प्रदान करे,

इस आधार पर शून्य होगा कि यह भारत के अन्य नागरिकों को इस भाग के किसी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार से असंगत है या छीनता है या कम करता है।

46. हम यह समझने में विफल हैं कि अनुच्छेद 35 इस मामले को आगे कैसे ले जाता है। यह अनुच्छेद केवल यह कहता है कि जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को राज्य में अचल संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय के साथ असंगत है। जम्मू और कश्मीर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 140 में उल्लिखित ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रदान करना इस आधार पर चुनौती का विषय नहीं है कि यह भारत के संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, नियम 8 (5) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अधिकार स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं।

47. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले में अंततः कहा गया है:

"यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केंद्रीय संसद के पास धारा 13, धारा 17 (क), धारा 18 (ख), धारा 34, 35 और धारा 36 में निहित कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है, जहां तक वे जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित हैं; आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उपरोक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 को जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है; आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के प्रावधानों का लाभ उन बैंकों

द्वारा उठाया जा सकता है, जो जम्मू-कश्मीर राज्य से उत्पन्न होते हैं और जो उन धन को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ताओं को दिए गए हैं, जो राज्य के विषय नहीं हैं और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी हैं और जो जम्मू-कश्मीर राज्य के गैर-राज्य विषय/गैर-नागरिक हैं और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य राज्य के निवासी हैं।

यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि सरफेसी के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता है, यह कहने के संदर्भ में एक विरोधाभास है कि सरफेसी का लाभ उन बैंकों द्वारा उठाया जा सकता है जो जम्मू और कश्मीर राज्य से उत्पन्न होते हैं, जो धन प्राप्त करने के लिए उनके बकाया हैं और जो उधारकर्ताओं के लिए अग्रिम किए गए हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी नहीं हैं।

48. इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं। नतीजतन, धारा 13 के संदर्भ में बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटिस और उक्त धारा के तहत किए गए अन्य दंडात्मक तरीके वैध हैं और आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तदनुसार अपीलों की अनुमति लागत के रूप में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों को स्वीकृति दी गई।

यह अनुवाद (पैनल अनुवादक) मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।